



मोदी सरकार एचएएल से खरीदेगी 97 नए फाइटर जेट

- वायुसेना को सितंबर में मिल सकते हैं 2 तेजस मार्क-1ए

नई दिल्ली (एजेंसी)। रक्षा सचिव आरके सिंह ने शनिवार को कहा कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सितंबर में भारतीय वायुसेना को दो तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमान सौंप सकता है। इन विमानों में वेपंस इंटीग्रेशन यानी हथियारों को जोड़ा भी किया गया है। इसके अलावा सिंह ने बताया, सरकार एचएएल के साथ 97 और तेजस खरीदने का नया करार करने जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 67,000



करोड़ रुपए होगी। फिलहाल 38 तेजस वायुसेना में शामिल हैं। इससे पहले न्युज एजेंसी ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया था कि केंद्र सरकार ने 19 अगस्त को भारतीय वायुसेना के लिए 97 एलसीए मार्क 1ए फाइटर जेट खरीदने के लिए 62 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। दरअसल, फरवरी 2021 में सरकार ने एचएएल के साथ 83 तेजस मार्क-1ए खरीदने के लिए 48,000 करोड़ का करार किया था, लेकिन एक अमेरिकी इंजन की डिलीवरी में देरी की वजह से अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट नहीं सौंप पाया। हालांकि, अब उम्मीद है कि 2028 तक सभी एयरक्राफ्ट्स वायुसेना को सौंप देगा। एलसीए मार्क 1ए, तेजस एयरक्राफ्ट का एडवॉंस वर्जन है। इसमें अपग्रेडेड एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगे हैं। एलसीए मार्क-1ए के 65 फीसदी से ज्यादा उपकरण भारत में बने हैं। तेजस को भी हाल ने डेवलप किया है। यह सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है।

आवारा कुत्तों ने मुझे दुनियाभर में किया फेमस

- जस्टिस विक्रम नाथ बोले-उनकी भी दुआएं मिल रही

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने शनिवार को कहा- मैं लंबे समय से कानून जगत में अपने छोटे-मोटे कामों के लिए जाना जाता था। मैं आवारा कुत्तों का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे न केवल देश में बल्कि दुनियाभर में फेमस कर दिया। केरल के तिरुवनंतपुरम में नेशनल लीगल सर्विस



अर्थोरीटी की तरफ से आयोजित मानव-वन्यजीव संघर्ष पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन में बोलते हुए जस्टिस नाथ ने कहा कि वह भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई को भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने यह कেস उन्हें सौंपा। दरअसल, 22 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर जहां से उठाया है, वहीं वापस छोड़ दिया जाए। ये आदेश दिल्ली समेत पूरे देश में लागू होगा। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा- इसके लिए नेशनल लेवल पर पॉलिसी बननी चाहिए। हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है। देश के बाकी हाईकोर्ट में जहां भी मामले लंबित हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए।

प्राइवेट अस्पतालों में नहीं हो रहा गरीबों का फ्री इलाज !

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है, जिसमें सरकारी जमीन पर बने या सरकारी रियायतों के आधार पर बने निजी अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को फ्री इलाज का मामला उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुआई वाली बेंच ने 29 अगस्त को इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। यह याचिका मैगसेसे पुरस्कार विजेता और इंटरनेशनल स्तर पर प्रसिद्ध एक्टिविस्ट संदीप पांडेय ने दाखिल की है। याचिका में यह मुद्दा उठाया गया है कि ऐसे निजी है अस्पतालों को सार्वजनिक जमीन

केंद्र-राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने थमाया नोटिस,मांगा जवाब



रियायती दरों पर इस शर्त पर दी गई थी कि वे गरीब श्रेणी के रोगियों को फ्री इलाज की सुविधा देंगे, लेकिन उन्होंने शर्तों का पालन नहीं किया। पीआईएल में कहा गया है कि राज्यों में लगातार ऑडिट रिपोर्ट, अदालत-निगरानी वाली जांचें और सरकारी अधिसूचनाएं यह दर्शाती रही हैं कि अस्पताल निर्धारित फ्री इलाज प्रतिशत (आमतौर पर 10 फीसदी इन पेशेंट बेड और 25 फीसदी आउट पेशेंट परामर्श) का पालन करने में लगातार असफल रहे हैं। यह सवाल उठाया गया है कि दिल्ली में कई अस्पतालों को शर्त थी कि वे अपने एक-तिहाई बिस्तर फ्री इलाज के लिए आरक्षित रखें।

कमरे में पत्नी का, पेड़ पर पति का शव मिला

मृतक के पिता ने कहा- बेटे ने बहू का गला दबाया, फिर बाहर जाकर आत्महत्या कर ली

दमोह (नम्र)। दमोह जिले के आंजनी की टपरिया गांव में शनिवार रात करीब 3 बजे दंपती में हुए विवाद के बाद पत्नी कमरे में मृत मिली और पति का शव घर के पास पेड़ पर फांसी के फंदे पर मिला। आशंका जताई जा रही है कि पत्नी की हत्या के बाद पति ने आत्महत्या कर ली। बटियागढ़ थाना पुलिस के मुताबिक, 30 वर्षीय मृतक विजय लोधे के पिता देव सिंह लोधे ने बताया- शनिवार रात मैं, पत्नी, बेटा और बहू चारों ने खाना खाया। मैं और मेरी पत्नी अपने कमरे में सोने चले गए। बाजू के घर में बेटा और बहू चंदा चले गए। रात करीब 3 बजे बहू के चिल्लाने की आवाज

सुनकर मैं उठा। दोनों को आवाज लगाई। घर की छज्जा पर जाकर देखा तो बेटा बहू का गला दबा रहा था। मैंने बेटे को चिल्लाया, लेकिन वह नहीं माना। जैसे-तैसे मैं दरवाजा तोड़कर घर में घुसा। बहू मृत अवस्था में पड़ी थी। बेटा वहां से भागने लगा। मैंने उसे पकड़ा तो उसने कहा कि मुझे मरना है। इसी बीच मैंने अपनी पत्नी से पड़ोसी को बुलाने के लिए कहा। जब तक मेरा पड़ोसी आया, मेरा बेटा मुझे धक्का देकर भाग निकला। मैं और मेरा पड़ोसी टॉच लेकर घर के पीछे गए तो वहां मेरा बेटा विजय पेड़ पर फांसी के फंदे से लटक मिला। उसकी भी मौत हो गई।



गणेशोत्सव पर सुंदरकांड

भोपाल । नीलबढ़ स्थित सिद्धिविनायक-तिरुपति कालोनी में गणेशोत्सव के चौथे दिन शनिवार को सुंदरकांड का आयोजन किया गया। जिसमें सभी कालोनीवासियों ने श्रीगणेश वंदना के बाद सुंदरकांड का आयोजन किया। जिसमें सभी रहवासियों ने धर्मलाभ प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण किया।

मनोज जरांगे का भूख हड़ताल और ज्यादा तेज करने का ऐलान

- मराठा आरक्षण आंदोलनकारी ने कहा-पानी भी नहीं पिएंगे

मुंबई (एजेंसी)। मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल ने आक्रामक रुख अपनाया है। वह ओबीसी कोटे से मराठा आरक्षण दिए जाने की मांग पर अड़े हैं। इसके लिए मराठों ने मुंबई के आजाद मैदान में एल्लार का आह्वान किया है। आज मनोज जरांगे पाटिल एस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं और अब और भी आक्रामक हो गए हैं। गुरुवार से भूख हड़ताल शुरू हो गई है। रविवार को भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। आज उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो भूख हड़ताल और भी कड़ा कर दिया जाएगा। जरांगे ने कहा है कि वह कल से पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे। मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे ने कहा कि कल यानी सोमवार से भूख हड़ताल और भी कड़ा कर दिया जाएगा। कल और आज मैंने पानी पिया, लेकिन सोमवार से मैं पानी नहीं लूंगा। मैं पानी पीना बंद कर दूंगा। सरकार सुन नहीं रही है। इसलिए मैं भूख हड़ताल और भी कड़ा करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने मराठों से अपील करते हुए कहा कि मराठा युवा ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनका सिर झुक जाए। सभी को शांत रहना चाहिए। उन्हें कोई भी अन्याय या अत्याचार करने दें। जरांगे ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि वह बिना आरक्षण लिए मुंबई नहीं छोड़ेंगे। जरांगे ने यह भी कहा कि अगर किसी को रेनकोट या छत्रा चाहिए, तो एक भी रुपया न दें। कुछ लोगों ने व्यवसाय शुरू कर दिया है। वे समाज के नाम पर कमाई कर रहे हैं। रेनकोट बांटने के नाम पर पैसा जमा न करें। मैं यह आखिरी बार कह रहा हूं। महाराष्ट्र में मराठा किसी को पैसा नहीं देना चाहते। केवल गरीबों की सेवा करना चाहते हैं।



इंदौर आ रही फ्लाइट लौटी नई दिल्ली में सेफ लैंडिंग

- एयरलाइन बोली-पायलट को इंजन में फायर इंडीकेशन मिला था; 90 यात्री सवार थे

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली से इंदौर पर जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट एआई 2913 (ए-320 निगो विमान) को दिल्ली लौटा लिया गया। पायलट को दाहिने इंजन में आग लगने की सूचना मिली थी। एअर इंडिया ने कहा- रविवार सुबह 6.15 बजे 90 यात्रियों के साथ प्लेन ने उड़ान भरी थी। करीब आधे घंटे बाद इंजन में फायर इंडिकेशन मिला। स्टैंडर्ड प्रोसेस के तहत पायलट ने इंजन बंद किया। बाद में प्लेन की एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग हुई। एयरलाइन ने कहा कि प्लेन का ग्राउंड इंस्पेक्शन कराया जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को भी घटना की जानकारी दी गई है। 29 अगस्त को भी दिल्ली से श्रीनगर आ रही स्प्राइजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। अधिकारियों ने बताया था कि फ्लाइट एआई 385 में



प्रेशराइजेशन की समस्या के कारण दोपहर 3.27 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया था। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि कॉकपिट कू को उड़ान भरने के तुरंत बाद दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत देखा। मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, चालक दल ने प्रभावित इंजन को बंद कर दिया और विमान को वापस दिल्ली ले गया। एयरलाइन ने पुष्टि की कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। टाटा समूह की स्वामित्व वाली एयरलाइन ने

कहा, 31 अगस्त को दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भरने वाली एआई 2913, उड़ान भरने के तुरंत बाद दिल्ली लौट आई, क्योंकि कॉकपिट कू को दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला। मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए, कॉकपिट कू ने इंजन बंद करने का फैसला किया और दिल्ली लौट आए, जहां विमान सुरक्षित रूप से उतरा। विमान को चेकिंग के लिए रोक दिया गया है, जबकि यात्रियों को इंदौर पहुंचाने के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई है।

पटना में ‘गांधी से अंबेडकर’ थीम पर निकलेगी यात्रा

- राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का जारी हुआ रूट मैप

पटना (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ रविवार की देश सभा पटना पहुंच गई है। इसके अगले दिन यानी सोमवार 1 सितंबर को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पटना में पैदल मार्च के रूप में निकाली जाएगी। यह पैदल यात्रा गांधी से अंबेडकर थीम पर निकाली जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ गांधी मैदान से होगा और समापन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्क में किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी को ओर से सोमवार को होने वाले मार्च का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक- राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के नेता सुबह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जुटेंगे। यहां 10.50 बजे 11.05 बजे तक महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद सुबह 11.15 बजे यहां से पैदल मार्च के रूप में वोटर अधिकार यात्रा का शुरुआत होगी, जो अंबेडकर पार्क तक जाएगी। गांधी मैदान से शुरू होकर वोटर यात्रा का मार्च दोपहर 12.30 बजे अंबेडकर पार्क पहुंचेगा। यहां राहुल गांधी- तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य सहित महागठबंधन के नेता बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 12.40 से 2.30 बजे के बीच राहुल गांधी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।



लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, बिल्डिंग उड़ी

फैक्ट्री मालिक-पत्नी समेत 4 की मौत, पड़ोसियों के घर टूटे

लखनऊ (एजेंसी)। लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में रविवार सुबह धमाका हो गया। हदसे में फैक्ट्री मालिक और उसकी पत्नी समेत 4 की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि, धमाके के बाद पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। बताया जा रहा है कि कई लोग मलबे के नीचे दबे हैं। डीएम-कमिश्नर मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस टीम में मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। धमाका इतना भीषण था कि आसपास के 2-3 मकान भी टूट गए। इससे करीब 10 लोग घायल हुए हैं। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही घायलों को स्थानीय लोग अस्पताल ले गए। बाराबंकी से भी फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच गई हैं। हार्दसा जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर गुडवा थाना क्षेत्र के बेहटा में हुआ है।



भारी वर्षा से जनजीवन अस्त-व्यस्त, सड़के जलमग्न हुईं, निचले इलाकों में पानी भराया

इंदौर। शनिवार दोपहर हुई तेज बारिश ने तपती गर्मी और उमस से लोगों को राहत दी। सुबह के बाद शुरू हुई बारिश घंटों तक लगातार जारी रही। बारिश से कई स्थानों पर जलजमाव के हालात बन गए। शहर में कई स्थानों पर नगर निगम की टीमों ने जल निकासी की। सबसे खराब हालात विजय नगर से पलासिया, रोबोट चौराहा, पलसीकर चौराहा, महु नाका और चंदन नगर इलाके के रहे। नगर निगम बारिश से पहले जिस तैयारी का दावा कर रहा था, उसकी पोल खुल गई। क्योंकि, सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। पिछले कई दिनों से लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। लेकिन, केवल हल्की-फुल्की फुहारों से ही मौसम गुजर रहा था। आज दोपहर एक बार फिर हुई झमाझम बारिश के बाद न सिर्फ मौसम सुहाना हो गया, बल्कि लोगों ने भी राहत की सांस ली। बारिश से जहां लोगों को उमस से राहत मिली, वहीं जाम के कारण यातायात प्रभावित रहा और लोगों

बारिश की नगर निगम की तैयारियों की पोल खुली, हालात बदतर



निगम की आपदा टीम मैदान में

तेज बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई। हालात को देखते हुए नगर निगम की आपदा प्रबंधन टीम, जोनल अधिकारी और कर्मचारी लगातार फील्ड में डटे रहे। टीमों ने अलग-अलग इलाकों में डी-वाटरिंग मशीनों की मदद से पानी की निकासी का कार्य किया। पलासिया चौराहे पर मशीन लगाकर पानी निकाला गया, वहीं वार्ड 81 स्थित नर्मदा चौराहे से रिंग रोड

गंगवाल-चंदन नगर रोड पर जाम

शनिवार की झमाझम बारिश से गंगवाल बस स्टैंड से चंदन नगर रोड तक लंबा जाम लग गया। सड़क पर पानी भरने से वाहन धीरे-धीरे चले और कई जगह जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने मोर्चा संभालकर जाम खुलवाने की कोशिश की।

तक भी निगम की टीम ने पानी निकालने का कार्य किया। बरसाना गार्डन और आसपास की कॉलोनियों में जलभराव की आशंका को समय रहते रोक दिया गया। इसी तरह जोन 7 और जोन 8, रोबोट स्कॉयर, जोन 13 मीरा गार्डन प्लाईट और पलसीकर कॉलोनी चौराहे पर जलभराव की स्थिति को निगम की टीम ने तत्काल कार्रवाई कर नियंत्रित किया। निगम अधिकारियों का कहना है कि बारिश के दौरान सभी जोंनों की टीमें अलर्ट पर हैं और किसी भी क्षेत्र में पानी भरने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर यातायात भी सुचारु हुआ। उधर, इंदिरा प्रतिमा के आगे पानी भरने से अग्रसेन तरफ रास्ता बंद, डायवर्ट करना पड़ा। नवलखा पर ट्रैफिक बढ़ा। स्वच्छ शहर की कॉलोनियों और गलियों में ड्रेनेज का पानी भरा।

डीएवीवी के आईईटी हॉस्टल में छात्र की रैजिंग और मारपीट का मामला गरमाया

छात्र ने कमोड में मुंह घुसाने का बयान बदला, मेडिकल से भी इंकार

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) के हॉस्टल में जूनियर छात्रों के साथ रैजिंग का मामला सामने आया। गुरुवार रात बीटोक थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हॉस्टल पहुंचे और परिचय के नाम पर एक जूनियर्स के साथ मारपीट की। पहले एक छात्र का मुंह कमोड में डालकर फ्लश चालू करने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में उसने इससे इनकार कर दिया। पीड़ित स्टूडेंट्स ने भंवरकुआं पुलिस से शिकायत की है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कुछ सीनियर स्टूडेंट्स की पहचान भी हो गई है, जिनसे आज पूछताछ की जाएगी। वहीं, रैजिंग के एक अन्य मामले में आईईटी ने 6 सीनियर स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निष्कासित किया है। बताया गया कि सीनियर्स हॉस्टल



पहुंचे और जूनियर से नाम पूछते हुए मारपीट की। घबराए हुए जूनियर स्टूडेंट्स ने अपने परिजनों और आईईटी प्रबंधन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद वे भंवरकुआं थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इस घटना के बाद से विवि और हॉस्टल में जूनियर घबराए हुए हैं। हॉस्टल के अन्य छात्रों का कहना है कि सीनियर ने एक छात्र का मुंह कमोड में डालकर फ्लश चलाया था, पूछताछ होने पर वह छात्र डर गया और उसने बयान बदल लिया। सोमवार तक जांच कर रिपोर्ट भेज देगे आईईटी के

प्रभारी डायरेक्टर डॉ प्रतोष बंसल ने बताया, घटना शुक्रवार शाम 4 बजे की है। पीड़ित थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। वह हॉस्टल गया था, तभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स से उसका इंटरव्यू हुआ और बात बढ़ गई। पीड़ित रोवा का रहने वाला है और यहां अलग से कमरा लेकर पढ़ाई कर रहा है। उसका आरोप है कि सीनियर्स ने उसे पीटा और कमरे में ले गए, वहां भी पीटा। घटना के समय हमारे कर्मचारी भी पहुंच गए थे और पीड़ित को लेकर आए। तब तक उसने अपने भाई को फोन कर दिया था।

इंदौर-मुंबई तेजस सुपरफास्ट ट्रेन के फेरे बढ़ाए

अब यह ट्रेन मुंबई से 12 और इंदौर से 13 सितंबर तक संचालित होगी



इंदौर। इंदौर-मुंबई के बीच संचालित हो रही सुपर फास्ट ट्रेन तेजस के फेरे विस्तारित किए गए हैं। यह ट्रेन अब 13 सितंबर तक संचालित होगी। पहले इसका संचालन 29 अगस्त तक होना था। यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन संचालित होगी। यात्रियों की मांग एवं सुविधा के लिए मुंबई सेंट्रल से इंदौर के मध्य चलने वाली मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित किए गए हैं। गाड़ी संख्या 09085 मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस स्पेशल ट्रेन 12 सितंबर तक मुंबई से प्रति सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 09086 इंदौर-मुंबई सेंट्रल तेजस स्पेशल 13 सितम्बर तक इंदौर से प्रति मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को चलेगी। वहीं उत्तर रेलवे जम्मू मंडल के कटुआ-माधोपुर पंजाब रेल खंड में ट्रैफिक सस्पेंड होने के कारण इंदौर से चलने वाली अम्बेडकर नगर से चलने वाली गाड़ी संख्या 12919 डॉ. अम्बेडकर नगर-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा एक्सप्रेस और श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्या 12920 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस 31 अगस्त को निरस्त रहेगी।

अवैध कड़ा और 5 खाली खोखे के साथ गिरफ्तार

इंदौर। पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से देसी कड़ा और 5 खाली खोखे बरामद किए हैं। कार्रवाई लसूडिया थाना पुलिस ने पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह और एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह के निर्देश पर की। पुलिस उपायुक्त जोन-2 हंसराज सिंह के मार्गदर्शन में गठित टीम को मुखबिंदर से सूचना मिली थी कि खालसा चौक सुलभ शौचालय के पास एक युवक हथियार लिए घूम रहा है। सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी करन कोरी (23) निवासी दतिया, हाल निवासी लसूडिया, को पकड़ गया। पुलिस ने उसके पास से कड़ा और 5 खाली खोखे जब्त कर आर्मस् एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी से अन्य आपराधिक गतिविधियों को लेकर पूछताछ जारी है।

ढाई लाख रु की अवैध शराब पकड़ाई

इंदौर। शनिवार को पार्सलों के बीच छिपाकर शराब ले जा रही एक आयरशर गाड़ी को जब्त किया गया है। द्वारकापुरी पुलिस ने गाड़ी को रोककर चेक किया तो उसमें ढाई लाख की 12 पेटो अंग्रेजी शराब मिली है। ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पार्सलों के बीच अंग्रेजी शराब भरकर फूटी कोटी ब्रिज की तरफ एक आयरशर गाड़ी आ रही है। पुलिस ने मोहन विला गार्डन के सामने मेन रोड चंदन नगर पहुंचकर नकाबंदी कर दी। कुछ दूर में गौपुर चौराहे की तरफ एक आयरशर गाड़ी (डीडी 01-सी9558) आई। गाड़ी को रोकने पर ड्राइवर ने अपना नाम विनोद सोनकर (48) निवासी यूपी बताया। उसने कहा कि गाड़ी में पार्सल भरे हैं। जिन्हें चेक किया तो पार्सलों के बीच में 12 क्विस्की शराब की पेटियां मिली हैं। जिनकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। अवैध शराब और ट्रक दोनों को जब्त कर लिया गया है। इनकी कीमत करीब 30 लाख रुपए है। ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है कि शराब कहाँ से आई और कहाँ जा रही थी।

झाकियों की तैयारी शुरू, पांच मिलों को

महापौर ने 2-2 लाख के चेक दिए

कहा कि निकलने वाली झांकियां इंदौर की सांस्कृतिक पहचान

इंदौर। शहर में परंपरागत अनंत चतुर्दशी पर्व की झांकियों का निर्माण शुरू हो गया। नगर निगम की ओर से झांकी निर्माण में सहयोग देने के लिए महापौर पुण्यमित्र भार्गव ने शहर की पांच प्रमुख मिलों (मालवा मिल, हुकुमचंद मिल, स्वदेशी मिल, राजकुमार मिल और कल्याण मिल) को दो-दो लाख रुपए के चेक दिए। यह झांकियां हर वर्ष बनाई जाती हैं। महापौर भार्गव ने कहा कि अनंत चतुर्दशी और इसके अवसर पर निकलने वाली झांकियां इंदौर की सांस्कृतिक पहचान हैं। न केवल इंदौर में बल्कि पूरे देश में अपनी भव्यता और परंपरा के लिए जानी जाती हैं। मिलों द्वारा बनाए जाने वाले ये स्वरूप शहर की ऐतिहासिक परंपरा को जीवंत रखते हैं। इसी कारण नगर निगम प्रतिवर्ष उन्हें आर्थिक सहयोग देता है, ताकि यह परंपरा निरंतर चलती रहे। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया भी उपस्थित रहे।

जन्मोत्सव समिति को भी सहयोग- महापौर ने देवी अहिल्या बाई जन्मोत्सव समिति को भी पांच लाख रुपए का चेक सौंपा है।

आज से रात 10 बजे तक खुलेंगी सोना-चांदी

इंदौर। अब देर रात तक राजवाड़ा क्षेत्र के बाजार में चहल-पहल रहेगी। सराफा व्यापारियों ने अन्य बाजारों के साथ सराफा भी रात 10 बजे तक खुला रखने की घोषणा की। एक सितंबर से इस पर अमल होगा। राजवाड़ा क्षेत्र के व्यापारियों ने इस मुद्दे पर चर्चा के बाद अपने सदस्य व्यापारियों के लिए सूचना जारी कर दी है। व्यापारी एसोसिएशनों द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में त्योहार और क्षेत्र के व्यापार को बढ़ाने को निर्णय का कारण बताया गया है। हालांकि असल कारण फुटपाथ व दुकानों के सामने कब्जे रोकना माना जा रहा है।

सराफा में लग रही चाट-चौपाटी के खिलाफ चांदी-सोना जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन ने असहयोग आंदोलन छेड़ रखा है। ओटलों पर क्रिएएदारी बंद करने के बाद सराफा बाजार में दुकानें रात 10 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को इंदौर रिटेल रेडीमेड गारमेंट व्यापारी एसोसिएशन ने बैठक के बाद इस पर सहमति जताई है। एसोसिएशन के सदस्य 600 गारमेंट कारोबारियों के साथ अन्य 300 दुकानदार भी देर रात तक दुकानें

व्यापारी संगठनों ने इसे अपना व्यापार बढ़ाने का निर्णय बताया



खुली रखने के लिए तैयार हो गए हैं।

व्यापारी कैविट दायर करेंगे

सराफा चाट चौपाटी के खिलाफ मुहिम चला रहे चांदी-सोना व्यापारी कानूनी तौर पर भी अपना पक्ष मजबूत करने में लगे हैं। बताया जा रहा है कि व्यापारियों पर कदम पीछे खींचने और दुकानें नौ बजे तक बंद करवाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया

आरटीओ की धार और पीथमपुर में कार्रवाई मारुति और होंडा टू-व्हीलर के शोरूम सील

इंदौर। आरटीओ ने पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र और धार शहर में वाहन डीलर्स पर बड़ी कार्रवाई की। आरटीओ हद्देश यादव ने शनिवार को नियम विरुद्ध संचालित हो रहे दो प्रमुख शोरूम धार के मारुति डीलर रुक्मणी मोटर्स और पीथमपुर के होंडा टू-व्हीलर डीलर राधा होंडा पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान दोनों शोरूम को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया।

परिवहन विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि ये शोरूम बिना आवश्यक ट्रेड सर्टिफिकेट और नियम के अनुसार दस्तावेजों के वाहन विक्रय कर रहे हैं। जांच में आरोप सही पाए जाने पर यह कठोर कदम उठया गया। आरटीओ ने बताया कि यह गंभीर अनियमितता है और नियमों के खिलाफ वाहन विक्रय किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



दोनों शोरूम को सील किया - आरटीओ ने धार में कार्रवाई के दौरान दो अन्य डीलर्स के यहां भी अनियमितताएं पाईं, जिन पर नोटिस जारी किया गया। उन्होंने साफ कहा कि यदि इन डीलर्स ने निर्धारित समय पर जवाब नहीं दिया और व्यापार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, तो उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ कार्यालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना व्यापार प्रमाण पत्र के वाहन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। नियमों का पालन किए बिना शोरूम संचालन अब सीधे तौर पर दंडात्मक कार्रवाई का

कारण बनेगा। **वाहन डीलर्स में मचा हड़कंप-** हद्देश यादव ने कहा कि जिले में व्यापारिक नियमों का पालन किए बिना वाहन विक्रय करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। भविष्य में यदि किसी भी डीलर द्वारा इस तरह की लापरवाही की जाती है, तो विभाग बिना किसी चेतावनी के सख्त कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई से वाहन डीलर्स में हड़कंप मच गया है और विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि आगामी दिनों में और भी सख्त चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।

चल समारोह से पहले ढहाए जर्जर मकान

इंदौर। नगर निगम ने शनिवार को झांकी मार्ग के जेल रोड क्षेत्र में स्थित लगभग 100 साल पुराने जर्जर मकानों को सुरक्षा की दृष्टि से ढहा दिया। निगम अधिकारियों ने बताया कि ये मकान काफी पुराने और जर्जर हालत में थे,जिससे चल समारोह के दौरान हादसे की आशंका बनी हुई थी। इस कारण त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें गिराया गया। निगम टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में मकानों को सुरक्षित तरीके से ढहाया गया।

परिवार के समझाने से नहीं रुकी श्रद्धा, करण के साथ ही चली गई

मित्रताों से नहीं पिघली, कहा ‘बचाई जान, उसके साथ रहूंगी’



के बाद उसके परिवार के लोग भी थाने आ गए थे। यहां पर श्रद्धा के पिता ने थाने में कई घंटों तक बेटी

कूदकर जान देने वाली थी श्रद्धा

करण ने पुलिस को बताया था कि श्रद्धा ट्रेन से कूदने की कोशिश कर रही थी। मैंने पूछा क्या कर रही हो, तो उसने कहा मर रही हूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं करने दूंगा। तब श्रद्धा ने कहा कि ऐसा ही मैंने कर लिया था। मैं तैयार हो गया, जिसके बाद दोनों खरगोन गए। वहां से मंदेश्वर पहुंचे और मंदिर में शादी की। फिर करण उसे अपने घर पालिया ले गया। घरवालों ने आपने से रोक दिया तो वहां से मंदसीर चले गए। वहां से श्रद्धा ने पिता को कॉल किया। ऑफिशियल रजिस्टर्ड मैरिज के लिए दस्तावेज मांगे, जिसके बाद श्रद्धा के पिता कार से उसे इंदौर लेकर आए।

से बातचीत कर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। उसने करण नामक जिस

युवक के साथ शादी की, वह उसके साथ ही जाने की बात कहती रही। काफी देर तक परिवार के लोग समझाते रहे। लेकिन, जब बात नहीं बनी तो श्रद्धा को युवक के साथ जाने दिया गया।

प्रेमी ने मिलने बुलाया, नहीं आया

एमआईजी थाने के टीआई ने बताया था कि श्रद्धा का सार्थक गेहलोत नाम के युवक से अफेयर चल रहा था। 23 अगस्त को उसने श्रद्धा को रेलवे स्टेशन पर बुलाया था। वह घर से स्टेशन पहुंच गई, लेकिन सार्थक नहीं आया। जिसके बाद श्रद्धा गुस्से में वहां खड़ी ट्रेन में बैठकर चली गई। ये ट्रेन रतलाम जा रही थी। युवती ने रतलाम में ट्रेन से कूदने की कोशिश की, तो किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। पलटकर देखा तो श्रद्धा का पूर्व परिचित करण योगी था, जो गुजराती कॉलेज में इलेक्ट्रिशियन रहा है।

संपादकीय

ट्रंप को भारत से नाराजी की वजह!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इतने खराब क्यों हैं, इसके पीछे के कारण का जो खुलासा वहां के अखबार 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने किया है, वह चौंका देने की बजाए अफसोसदायक है। अखबार के मुताबिक ट्रंप और चीनराना सिद्धू के बाद पाकिस्तान व भारत के बीच संघर्ष को रूकवाने का श्रेय लेना चाहते थे कि पाकिस्तान की तरह भारत भी उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नामांकित करे। भारत ट्रंप के इशारे की भांग गया था। उसने न केवल संघर्ष विराम कराने के ट्रंप के दावों को खारिज किया बल्कि नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करने की अपेक्षा को भी रद्दी की टोकरें में डाल दिया। शांति इसी वजह से ट्रंप नाराज हैं और मनमानी किए जा रहे हैं। अखबार के मुताबिक ट्रंप का भारत के प्रति रवैया 17 जून के एक फोन के बाद कड़ोर होता चला गया। 17 जून को जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष पूरी तरह रुक चुका था तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया। इस फोन में उन्होंने दावा किया वह दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष खत्म कराने के लिए गौरवान्वित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने वाला है। एनवाईटी के मुताबिक, यह पीएम मोदी को सीधा इशारा था कि वह भी ऐसा ही करें। अखबार ने इस फोन कॉल की जानकारी रखने वालों के हवाले से दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे बिस्वकुल सहमत नहीं थे। उन्होंने ट्रंप से सफा शब्दों में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया संघर्ष विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं रही। यह भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी बातचीत के बाद हुआ है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को नज्दअंदज करने की कोशिश की। हालांकि, भारतीय पीएम की तरफ से जताई गई अहमदमति और नोबेल शांति पुरस्कार के मामले में कुछ न कहना, दोनों नेताओं के रिश्तों में खटास पैदा कर गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस फोन कॉल पर उसकी रिपोर्ट अमेरिका से लेकर भारत तक दर्जन भर अधिकारियों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। इसमें से अधिकतर लोगों ने अपनी नामों का खुलासा न करने की शर्त पर अखबार से बात की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सबसे अहम साझेदार के साथ रिश्ते खराब करने की कोशिश में जुटे हैं। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं, जिनकी वजह से ट्रंप और मोदी के रिश्ते बिगड़े। ये हैं अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के निर्वासन व एच एन बी वीजा की समीक्षा का मामला, ट्रंप द्वारा वाशिंगटन आने के न्यौते से मोदी का इंकार, अतिरिक्त टैरिफ लगाने के मुद्दे पर भारत नाराज समझौते की पहल न करना, व्यापार समझौते के लिए मोदी द्वारा ट्रंप का फोन न उठाना शामिल है। इस बीच भारत अपनी विदेश नीति की फिर से समीक्षा करके रूस, चीन, भारत गठजोड़ को मजबूत करने में लग गया है। अमेरिका को इससे भी पक्की लगी है। संदेश साफ है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में न तौले और ट्रंप फोकराद का श्रेय न ले। जहां तक नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप के नामांकन का सवाल है तो उन्होंने ऐसा किया ही क्या है कि भारत उन्हें विश्व के इस सबसे बड़े पुरस्कार के लिए नामांकित करे। वो केवल धमकियां देने का काम कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार इस योग्यता के लिए तो नहीं मिलता। इस बीच यह खबर भी आई है भारत से चिट्ठे ट्रंप इस साल भारत में होने वाले क्राइ समेशन में भाग लेने नहीं आएंगे। अमेरिका याद रखे कि यदि भारत क्राइ में निष्क्रिय हुआ तो उसकी ओर अहमियत नहीं रह जाएगी।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

रात सरकार ने अचानक 20 अगस्त को संसद में एक बिल प्रस्तावित किया जिसे 130 बां संधिवधान संशोधन विधेयक 2025 बताया गया। इस संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से यह प्रस्तावित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी संसधानिक पद पर है गिरफ्तार किया जाता है और 30 दिन में वह जमानत या अन्य कारण से जेल के बाहर नहीं आता तो उसे अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। संशोधन विधेयक पेश करने हुए गृहमंत्री जी ने कहा कि यह विधेयक सार्वजनिक जीवन में श्रुचिता लायेगा और इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी कोई छूट नहीं है। यानी यह निम्नस्व विधेयक है। इस विधेयक का प्रतिपक्षी दलाने ने विरोध किया। आमचलन के अनुसार जोदरदर हंगामा हुआ और विधायक को विचारार्थ संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल 29 लोग होंगे और संसदीय परंपरा के अनुसार स्वाभाविक है कि इसमें सत्ता पक्ष के लोग उसकी संख्या की तुलना के अनुसार न्यूनदा होंगे। इस समिति के संघर्ष के अगले सत्र के पहले दिनांक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

प्राप्यपक्षी दलों का कहना है कि यह संशोधन संसोधन का अर्थात विरोधी दलों की सरकारों को अस्थिर करने और उद्धे भ्रष्टाधीत करके के उद्देश्य से लाया गया है। विरोधी दलों का संशय भी निराधार नहीं है और सत्ता पक्ष के लिए पिछले दिनों की कुछ घटनाएं मजबूत तर्क के रूप में हैं। जिन्हें उद्धृत कर लुग श्री अमित शाह गृहमंत्री ने संसद में कहा कि कुछ लोग ऐसे से सरकार चलाते हैं। मुख्यमंत्री या मंत्री के पद पर रहते हुए जेल जायें पर भी इस्तीफा नहीं देते और नैतिक मानदंडों का पालन नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि जब मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो मैंने इस्तीफा दे दिया था और मुकदमे के खान्ते के बाद भी पुनरा सरकार में आए। एक कथन में उनका यह कहना भी है कि वर्ष 2020 तक यह परंपरा रही है कि अगर कोई मंत्री गिरफ्तार होता था तो वह इस्तीफा देता था। क्योंकि एक संसदीय व्यवस्था में एक व्यक्ति किसी अपराध के संशय में संसद में जाता है तो उसका पद बने रहना संसदीय व्यवस्था पर और नैतिकता के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। इस संशोधन विधेयक के पेश होने के बाद सारे देश में और मीडिया में भी बहस चल रही है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री ए. के. पेननायक ने भी इस विधेयक को असंवैधानिक बताया है और उनका मत है कि सर्वोच्च न्यायालय इसे खारिज करेगा ऐसा उनका मत है। उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र के हाथ में सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां हैं जो सुनिश्चित कर सकती हैं कि किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को कितने दिन जेल में रहना है। इससे केंद्र सरकार मुख्यमंत्री या मंत्रियों का पद छीन सकेगी यदि सरकार कमजोर हुई तो मुख्यमंत्री के हटते ही डगमगा

वागर्थ

संविधान संशोधन एक चतुराई भरा कदम

पिछले दिनों जिस प्रकार सरकार ने ईडी सीबीआई आदि संस्थाओं का दुरुपयोग किया है उससे प्रतिपक्ष की चिंता भी निराधार नहीं कहें जा सकती। कितना विचित्र है कि दो-दो साल तक मंत्री जेल में रहे और उसके बाद भी एजेंसी अपराध का कोई प्रमाण न दे सके और फिर स्वतः खात्मा लगा दें। होना तो यह चाहिए कि एजेंसी पहले प्रमाण जुटाए तब गिरफ्तार करें न कि प्रमाण मिलने के पहले ही गिरफ्तार करने के अवैधानिक हथियार की शक्ति का प्रयोग करें। एजेंसी घटनाएं कोई एक दो नहीं है बल्कि बहिसियाँ हैं। ऐसी भी घटनाएँ सामने आई हैं कि जहाँ किसी विरोधी पक्ष के नेता के सप्ताधारी दल में शामिल होने के बाद उसके खिलाफ एजेंसी स्वतः अपना केस वापस ले ले और खात्मा लगा दें।

जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अतीत में देखा गया है कि कोई मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन से अधिक जेल में रह लें किन उनके खिलाफ आज तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि अगर कोई मंत्री और मुख्यमंत्री वही होते हैं तो सूर्य फसाले वाले उन अधिकारियों व एजेंसियों के मुखिया और सरकार के पीएम सीएम भी जेल भेजे जाएं। भाजपा का और से अधिकृत या अनाधिकृत रूप से राज्यसभा के पूर्व महासचिव श्री बी. के. अग्निहोत्री ने कहा है कि राजनीतिक शुचिता को दृष्टि से यह अच्छा कदम है। अगर कोई सिविल सर्वेंट किसी भी कारण से 48 घंटे से अधिक जेल में रहता है तो सिविल सेवा के नियमों के तहत उन निलंबित मान लिया जाता है। जमानत के बाद भी उस बहाली के लिए मशकत करनी पड़ती है। अगर को सीएम या मंत्री जेल में रहने के चलते कुर्सी गवाता है तो पार्टी किसी और नेता को सीएम या मंत्री बना सकती और पार्टी सत्ता में रहेगी। इसलिए इस उपाय का स्वागत किया जाना चाहिए। श्री अग्निहोत्री ने तो तर्क निराधार लगाने हैं। अधिकारी का निलंबन होता है और अगर उस बहाली के लिए मशकत करना पड़ती है तो यह नियम कायदों की खामी है और सक्षम अधिकारियों का कदमरफ्त है। इस बरस को अगर बारीकी से देखा जाए तो इसका मूल कारण तो सत्ता के प्रति और सरकार एजेंसियों के प्रति विश्वास है जो की स्वाभाविक ही है।

पछले दिनों जिस प्रकार सरकार ने ईडी सीबीआई और
संस्थाओं का दुरुपयोग किया है उससे प्रतिपक्ष की चिंता
भी निराशर नहीं करती जा सकती। कितना विचित्र है कि ए
दो-दो सालत कहीं कहीं जेल में रहे और उसके बाद
एजेंसी अपराध का कोई प्रमाण न दे सके और फिर स्वतः
खात्मा लगा दे। होना तो यह चाहिए कि एजेंसी पहले
प्रमाण जुटाए तब गिरफ्तार करे न कि प्रमाण मिलने से
पहले ही गिरफ्तार करने के अवैधानिक हथियार को शक्ति
का प्रयोग करे। ऐसी घटनाएँ क्यों एक दो नहीं है बल्कि
बीसियों हैं। ऐसी भी घटनाएँ सामने आई हैं कि जहाँ किसी
विरोधी पक्ष के नेता के सत्ताधारी दल में शामिल होने से
बाद उसके खिलाफ एजेंसी स्वतः अपना केस वापस ले
और खात्मा लगा दें। महाराष्ट्र एनपीसी के नेता और शरा
पवार के भतीजे श्री अजीत पवार के खिलाफ 1000 को
के भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा ने और सीबीआई ने भ
लगाए थे परंतु जब वे एनपीसी छोड़कर भाजपा में शामिल
हो गए तो सीबीआई ने खात्मा लगा दिया और श्री पवार क
मंते बना दिया। जब वे पुनः भाजपा छोड़कर एनपीसी
चले गए तो केंद्र के इशारे पर सीबीआई ने फिर उन
खिलाफ प्रकरण शुरू करने की अर्जी लगा दी। और फिर

जब वे पुनः भाजपा के समर्थन में चले गए तो न केवल उपमुख्यमंत्री हैं बल्कि इस एजेंसी ने फिर मालता वापस कर लिया। लगभग ऐसी ही घटना प्रफुल्ल पटेल की भी है जो एनसीपी के पक्ष से हट कर सरकार में मंत्री थे। कैंद सरकार एजेंसियों का इस प्रकार बेशर्म प्रयोग राजनीतिक भयादौहन और दल बल्ल कवाने के लिए करती रही है। अतः कहेंद सरकार को नितय और सत्ता को दास एजेंसियों को कानावाही कैसे विश्वासयोग्य मानी जा सकती है? जो लोग निष्पक्षता या शुचितता का तर्क दे रहे हैं वह तर्क पढ़ने और सुनने में अच्छा लगता है, परंतु देश में नैतिकशाही का जो चरित्र है उसमें क्या उससे यह उम्मीद की जा सकती है कि वह प्रथमार्थी या मुख्यमंत्री या सत्ता पक्ष के मंत्री के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे? कुल मिलाकर अभी तक के राजनीतिक अनुभव और आम तौर पर सभी सरकारों के चरित्र को देखते हुए इस प्रावधानों की शक्यवली और शुचितता के दावे पर कुछ विश्वास किया जा सकता है? फिर दूसरा एक वैधानिक, नैतिक और तार्किक सवा भी है, कि क्या किसी व्यक्ति को किसी एजेंसी के द्वारा आरोपी बना दिए जाने मात्र से उसे दोषी मान लिया जाए। दोषी सिद्ध करने का अधिकार न्यायपालिका का है। अभी तक यह कानून है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो वह पद पर रहने के अवसय हो जाता है परंतु इस संशोधन से तो केवल आरोप लगने पर ही व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाएगा और पद से हटने के दंड का भारी मान जाएगा। यह संशोधन न्याय के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है। श्री अमित शाह का राजनीतिक जीवन आपातकाल के बाद का है परंतु उन्हें अपनी मातृ संस्था के प्रमुखों से जानना चाहिए कि जिस आपातकाल के वे विरोध करते हैं और कांग्रेस के द्वारा लगाए गए जिस आपातकाल ने उनके और उनकी पार्टी के लिए सत्ता के दरवाजे खोले हैं उसमें क्या हुआ था? जब सरकार का आदेश हुआ कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, मोरारजी देसाई को गिरफ्तार करना है और आरोप बनाने और लगाने का काम सरकारी एजेंसी को करना है तो पुलिस ने जयप्रकाश नारायण को राजद्रोह का अपराधी और पुलिस तथा सेना में विद्रोह फैलाने का उन्तरदायी बता दिया था। मोरारजी देसाई को तो यह आरोप पत्र दिया गया था कि वह सरकार के उद्दीपीकरण के खंभे पर चढ़कर तारा काट रहे थे इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उस पुलिसकर्मी का कोई दोष नहीं है क्योंकि उसे तो झूठ आरोप लिखना है। केंद्रीय जांच एजेंसियां और पुलिस लगभग सत्ता पक्ष के सही या गलत आदेशों का पालन करने वाली बन जाती है। मेरी राय में शुचितता और नैतिकता के लिए कानून बनाया जाए तथा कानून निम

प्रकार का हो सकता है।

- न्यायपालिका को 29 दिन में निर्णय देने की वाध्यता हो और उसके बाद आगामी 30 दिनों में अपीलयाय न्यायपालिकाएं आवश्यक निर्णय करें। अगर न्यायपालिकाएं अंतिम अपीलयाय स्तर पर किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को दोषी सिद्ध करें तब उसे इस्तीफा देने या हटाए जाने का नियम बने।
2. यह भी कानून बने कि जो एजेंसियां गिरफ्तार करने के 7 दिन के अंदर बालान पेश करें। अगर नहीं कर पाती हैं या न्यायपालिका को संतुष्ट करने लायक प्रमाण पेश नहीं कर पाती हैं तो प्रकरण को निरस्त किया जाए।
3. जो जांच एजेंसियां आरोप ला रही हैं और अगर वे निर्णय के पूर्व यह स्वीकार करती हैं कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो गिरफ्तार करने वाली एजेंसी के मुख्य अधिकारी को दंडित किया जाए।
4. अगर न्यायपालिका अपने फैसले में यह दर्ज करती है की जांच एजेंसी ने जानबूझकर लापरवाही की है या किसी के दबाव में आकर झूठी कार्यवाही की है, तो उस एजेंसी के जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हो तो गैर जमानती हो।
5. सुचित के लिए यह भी संवैधानिक प्रावधान बने कि अगर सत्ता पक्ष अपनी सरकार के विरोधी व्यक्ति या राजनीतिक व्यक्ति पर उनकी जांच एजेंसी के द्वारा आरोप लगाने के बाद, उसे अपने पक्ष में शामिल करती हैं तो उसे राजनीतिक अपराध माना जायेगा तथा उस सत्ताधारी पार्टी को जिम्मेदार मानकर उसकी मान्यता समाप्त की जायेगी। भारत सरकार के 130 वें संविधान संशोधन से जितने भयभीत सत्ता पक्ष इस संघर्षालक गुट से भिन्न सत्ता के लोग हैं। क्योंकि इस संशोधन के हथियार का इस्तेमाल जितना प्रतिपक्ष के खिलाफ हो सकता है उतना ही सत्ता पक्ष के अंतर् विरोधियों के खिलाफ भी हो सकता है। प्रतिपक्ष तो कम से कम आलोचना भी कर सकेगा पर सत्ता पक्ष का अंतर्विरोधी तो यह भी नहीं कर सकेगा। यह संशोधन एक भयावह तानाशाही और लोकतंत्र के खान्धे का कारण बन सकता है।
- इसहाल यह संशोधन होगा या नहीं होगा यह तो अभी पवित्र के गर्भ में है तथा मीडिया और जनता में चर्चा में है। भुंति एक लाभ तो प्रधानमंत्री, गुहर्षी की और जनता पार्टी को हो ही गया है कि जो मीडिया वोट चोरी के आरोपी की चर्चाओं से भरा हुआ था अब वह इस संशोधन की आड़ में पीछे छूट गया। यह संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव एक दूरदर्शी भार राजनीतिक षड्यंत्र है, यह शायद प्रतिपक्ष भी नहीं समझ पाया।

शवाहन बनने की एक कथा

हलात। अरे ! जरा भारत को देखो, पूरे देश में लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, किन्तु देश के नेता केवल आपस में लड़ रहे हैं। संसद चले-जा-चले, सत्ता पाने के लिए अथवा अपने वेतन बढ़ाने के लिए सारे नेता एकमत हो रहे हैं। खैर, आप निश्चिंत रहें, कल तब हमें इसका हाल होगा जाणी। स्वर्ग को, चूहे से निजात मिल जाएगी। यह सुनकर देवता प्रसन्न हो गए, चूहे की समस्या से निश्चिंत हो गए। मार, अथ श्रीगणेश प्रणाम हो गए। सोचने लगे, आखिर चूहे का क्या किया जाए? चूहे को स्वर्ग से कैसे विदा किया जाए? शिवपुत्र विचार करते लगे, चूहे को धिक्कारने लगे। अंत में, एक विचार आया, दूत को भेजा और चूहे को अपने महल बुलावाया। चूहे के वहाँ पहुँचने पर, गणेशजी को दूतों ने की उसकी अगुवाई, गणेशजी ने उसे चाकर पिलावा। चारों पिलाते ही उसे सम्झाया, तुम्हें सफल स्वर्ग में रहना है या कुछ इज्जत भी पाना है। इज्जत की बात पर चूहा गदगद हो गया, और इसी खुशी में वह चूहा, गणपतिजी का प्राशन करने को तैयार हो गया। दूसरे दिन स्वर्ग की सभा ने यह प्रवचन पास कर दिया और उसी दिन से वह चूहे बनकर गणेशजी का परमांतन हो गया। वाहन चढ़ने लगा, समय गुजरने लगा। पिछले साठ के दशक की बात है, चूहे को स्वर्ग की एक परी सफल आई, श्री गणेश ने उस परी से चूहे की शादी करवाई। शादी का हुं, इंद्रलोक में उस परी आफत आ गई, तीनों माह में ही स्वर्गलोक में चूहे की बाढ़ आ गई। किन्तु अबकी बार इन्द्र ने भी एक जुगाड़ बिछाई, चूहों को ईंसान बनाकर, पहली खेप भारत भिजवाई। तब से- प्रत्येक त्रेमास में ईंसान रूपी चूहों की खेप भारत आ रही है और देश में लाख प्रयास के बावजूद जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है।

मैं अपनी तथा देश की एक सौ चालीस करोड़ जनता की ओर से भावार्थ गणेश से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ - हे गणपति जी, स्वर्ग से दर्जनों बच्चे मृत्युलोक एक-एकपट्टे हो रहे हैं, इन इंगोटेंड बच्चों से आपके भक्तगण परेशान हो रहे हैं, सम्मेलन पर सम्मेलन हो रहे हैं, मगर बच्चे फिर भी बढ़ते ही जा रहे हैं, खाद्यान्न के भंडार समाप्त हो रहे हैं, किन्तु बच्चे तो प्रति घंटे आठ सौ से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ते ही जा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया हमारी समस्या पर भी गौर करना, किफा फार्मूले से हमारा भी उद्धार करना और हँ, स्थिर लगे तो कह देना। कितने लो से सिंदूर चढ़वाऊंगा, सम्मेलन समाप्त होने पर कृपया पाठक से 5001 के लड्डू और मोदक चढ़वाऊंगा।

अंजना दिया। लेकिन उसकी इस पॉलिस्की में साफ-सुथरी आर्थिक दृष्टि नहीं दिखती। अमेरिका की इस पॉलिस्की में लेबल पॉलिटेस्टिक की गंध आती है। ऑपरेशनसिंदू में भारत ने उनकी कृमिका खारिज कर दी तो चिड़ गया भारत, रूस से लेते लेना वहां नही भूमिका तो उसका हित टकरा गया। उसमें चीन के खिलाफ जहां 30 फ्रीवैट टैरिफ लगाया वहीं भारत के खिलाफ 50 फ्रीवैट। यह टपू को पारदर्शी टैरिफ नीति नहीं है। टपू ने भारत के खिलाफ अपनी खंडी और गुस्से का प्रदर्शन किया है। लेकिन भारत भी अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है।

भारत समेत बिस्वस संचटन में शामिल स्वरा अमेरकी डूलरत पर भनितरत कतारत चाहते हैं। संचटन में भारत स्वरा अग्रणी। अमेरकीता चाहते हैं भारत कतारत अरु कृषी और उद्यर्य डवरी में टैरिफ कम करे लेंकिता भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। जिसका नतीजा हुआ टुंग ने टैरिफ बम भारत पर फोड़ दिया।

हलाकि इसका दुष्प्रभाव एक पक्षीय नहीं होगा। यह अलग बात है कि भारत को समसे अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन टुंग की इस टैरिफ नीति ने भारत के साथ दुनिया के देशों को एक कड़ संदेश दिया है। संदेश सरफ है कि समरा अधिक आत्मनिर्भरता को हर हाल में खत या कम नुकसान के लिए व्यय नहीं बदलना लाता होगा। हलाकि अमेरिका ने इस आर्थिक अंग छेड़े है उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगाना पड़ेगा। इसका असर सिर्फ व्यापार क्षेत्र में ही नहीं पड़ेगा। समरकि संबंधों और वैश्विक कूनीति पर भी थिड़ेगा। जिसके बाद एक ग्लोबल स्तर पर तनाव को स्थिति बननी। दुनिया को इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी अमेरकी की होगी।

उठाना पड़ेगा। भारत से करीब 28 फीसदी वक्त्र, कालोन का निवास अमेरिका को होता है। भारत के संपूर्ण व्यापार निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 20 फीसदी है। भारत की जीडीपी में अमेरिका के योगदान हैं। यह मानना ज़रूर है कि भारत को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। लेकिन बयाना अधिक के सामने झुटना भी भारत का ठीक है। समस्याएं आती हैं तो हमें समस्या की तलाश होनी चाहिए। जिसकी पृष्ठभूमि तय करने में भारत जुड़ें। हालांकि दुर्घ के वक्त्र में भारत में नैतिकता भी का बहुत बड़ा है। कई लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। श्रमप्रधान सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान का प्रभाव दिख सकता है। रैमकटाल, आभूषण, कृषि रज जैसे सेक्टर में यह स्थिति दिखाई देती। केंद्र की मोदी सरकार इससे से निपटने के लिए रणनीति भी बना रही है। फिर भी अगर अमेरिका के साथ बंधों में कोई समझौता न हुआ तो भारत को आर्थिक नुकसान तो उठाना पड़ेगा। भारत को अब हर हाल में अमेरिका पर निर्यात को कम करनी होगी। धारणीयता का जापान इसी बाद चीन देश इसका संकेत है। वहां चीन की रणनीति जिनगी और हस्की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कुछ नया खुल गिला। ग्लोबल ट्रेड पर कोई नया फैसला हो सकता है। अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ एक मजबूत रणनीति बन सकती है। अगर तीनों देशों की तितकड़ी सफल हो गई तो में भविष्य में अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान उठान पड़ सकता है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए टैरिफ नीति को

बाद दू पाँचों और मजबूत होंगे।

अमेरिका की इस पॉलिसी से भारत जैसे देश उसके खिलाफ हो गए। जिस चीज को वो सबक सिखाने के लिए वह भारत के साथ खड़ा था। वहीं चीन और भारत अब अमेरिकी नीति के खिलाफ एक मंच पर आ रहे हैं। दक्षिण एशिया की दो महाशक्ति एक मंच पर आ रही है तो दुनियाँ में कुछ नया होने वाला है। हाजिरमैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन की खाम पकड़ है। इसका बावजूद नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। इसका असर पड़ने अमेरिकी नीतियाँ पर ही नहीं ग्लोबल वार, हथियार की होड़ और आर्थिक नीति पर भी पड़ेगा। ट्यू के आगे भारत के ना झुकने की पॉलिसी ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। दुनियाँ में सबसे अधिक भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया गया है। ट्यू की कोरी नीति आर्थिक रूप से भारत को कमजोर तोड़ने की सजिश है। ट्यू भारत को झुकाना चाहते हैं और पाकिस्तान की तरह खुद का पीछलगू बनाना चाहते हैं। लेकिन भारत के लिए यह संभव नहीं है। भारत की दुनियाँ में एक साख है। उसके पास विपुल आर्थिक संसाधन हैं। कृषि आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था उसका बेहद मजबूत आधार है। ऐसे हालातों में भूखरीबी के खलाक बनने से रहे आर्थिक नुकसान भले उठाना पड़े। फिर भारत क्यों झुकेंगा।

कॉफी विस्लेणन और मीडिया टेरेस्ट में यह बताया गया है कि भारतीय नियाँ पर काफी असर पड़ सकता है। टैरिफ्स, कृषि उत्पादन, आनिमेट, चमड़ा, पेट्रोलियम, केमिकल्स और मेडिकलिन बाजार को काफी नुकसान

सामयिक

प्रभुनाथ शुक्ल

लेखक पत्रकार हैं।

मेरिका की टैरिफ पॉलिसी से 'ग्लोबल ट्रेड' को लेकर एक नई बहुत छेड़ दिया है। अमेरिका को यह आर्थिक नीति दुनिया को कहाँ ले जा रही है, अमेरिका में मंच बड़ा सवाल है। खुद अमेरिका को लिए यह आर्थिक और सामरिक संबंधों पर किन्तनी समझदारी होनी यह बक नालागा। ट्रेड इस आर्थिक नीति से अमेरिका को कितना कमाए कर पावे हैं यह देखना होगा। लेकिन ट्रेड की दाढ़ीगरी ने ग्लोबल ट्रेड नीति को बड़ा झटका दिया है। अत्यधिक टैरिफ को मार झरोटे रहे भारत, चीन और रूस जैसे देश नई व्यापार नीति को अंगमने देते लिए एक मंच पर आ रहे हैं। यह दक्षिण एशिया के लिए जहाँ सुपरद है। दूसरी तरफ अमेरिका के प्रथम के लिए प्रचलित है।

अमेरिकी अदालत ने ट्रांफो टैरिफ नीति को खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद ट्रांफो को बड़ा झटका लगा है। सरकार अदालत के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। यह ट्रांफो की विदेश नीति के खिलाफ बड़ा फैसला है। अदालत ने ट्रांफो प्रशासन को 14 अक्टूबर तक का समय दिया है, सरकार इसमें खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। दुनिया के देशों के लिए यह सुबक फैसला है। क्योंकि अमेरिका में खुद ट्रांफो अपनी आर्थिक नीति की आलोचना ज़ोर रहे हैं। दूसरी तरफ अदालत के फैसले के

सुबह सवरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबन्धु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MP/INH/ 2015/ 66040
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं।
इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।



उच्चतम न्यायालय फिलहाल राष्ट्रपति के द्वारा पूछे गए 14 प्रश्नों की सुनवाई कर रहा है। आईये जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय में इन प्रश्नों पर हुई सुनवाई में क्या कहा गया है। यह प्रश्न भी उठा कि राज्यपाल अगर अनुमति रोककर विधेयकों पर वीटों लगा सकते हैं तो इससे मनी बिल भी अवरूद्ध हो सकते हैं। राष्ट्रपति संदर्भ सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 200 की इस व्याख्या पर चिंता व्यक्त की कि राज्यपालों को किसी विधेयक को राज्य विधानसभा को वापस भेजे बिना उसे रोकने का स्वतंत्र अधिकार है। यदि इस व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि राज्यपाल धन विधेयकों को भी रोक सकते हैं, जिन्हें अन्याय स्वीकृत करने के लिए वे बाध्य हैं। यह सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति चंडुरकर की संविधान पीठ के समक्ष हो रही है।

महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे की बहस के दौरान उन्हें संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने केन्द्र सरकार के इस तर्क का उल्लेख किया कि अनुच्छेद 200 (1) के तहत रोकें रखने की शक्ति को अनुच्छेद 200 के प्रावधान के अनुसार विधेयक को विधानसभा को वापस भेजने के विकल्प के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है। केन्द्र सरकार के अनुसार यदि राज्यपाल किसी विधेयक को रोक लेता है, तो इसका अर्थ है कि वह विधेयक निरस्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल रोककर विधेयक पर वीटो लगा सकते हैं। केन्द्र सरकार तमिलनाडु राज्यपाल और पंजाब राज्यपाल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से असहमत है कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक को रोक लेता है तो उसे पुनर्विचार के लिए उसे

संदर्भ- राष्ट्रपति के सवाल-1

विधेयकों पर अनुमति के मुद्दे पर राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 200 की इस व्याख्या पर चिंता व्यक्त की कि राज्यपालों को किसी विधेयक को राज्य विधानसभा को वापस भेजे बिना उसे रोकने का स्वतंत्र अधिकार है।

विधानसभा को वापस भेजना आवश्यक है। बहस के दौरान न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि ‘‘केन्द्र का कहना है कि रोक लगाने की शक्ति अपने आप में स्वतंत्र है और राज्यपाल विधेयक को रोक सकते हैं। इसलिए जब आप स्वतंत्र रूप से रोक लगाने की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो यह थोड़ा समस्याग्रस्त होता है। क्योंकि, राज्यपाल विधेयक को शुरुआत में ही रोक लेते हैं। समस्या यह है कि इस शक्ति के साथ धन विधेयक को भी रोका जा सकता है। यह प्रावधान यहां लागू नहीं होगा। इस व्याख्या में एक बड़ी समस्या है। एक क्षण के लिए यह मान भी लें कि यह अनुमति है तो शुरुआत में भी विधेयक को रोका जा सकता है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि अनुच्छेद 200 के प्रावधान में कहा गया कि धन विधेयक के मामले को छोड़कर राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा सकते हैं। ‘न्यायमूर्ति ने कहा कि यदि राज्यपाल को विधेयक रोकने की स्वतंत्र शक्ति प्राप्त है तो धन विधेयक को भी तुरंत रोका जा सकता है। वह धन विधेयक को तुरंत रोक सकते हैं।’ इस पर प्रसिद्ध अभिभाषक हरीश साल्वे ने उत्तर दिया कि वह ऐसा कर सकते हैं। साल्वे ने कहा कि अगर कोई अनुच्छेद 200 की स्पष्ट भाषा को बिना किसी पूर्वधारणा के पढ़े तो यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को आसानी से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 200 का मूल प्रावधान यह नहीं कहता कि राज्यपाल धन विधेयक को रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं, वह यह है कि हम प्रावधान के बाहर से शब्द चुन रहे हैं और उन्हें प्रावधान से जोड़ रहे हैं। क्योंकि, हमें लगता है कि कुछ सीमाएं होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि रोकना राज्यपाल के पास स्वीकृति देने, विधानसभा को वापस भेजने और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए

आरक्षित रखने के अलावा चौथा विकल्प है। इस पर न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने फिर पूछा कि आप इस बात को कैसे संतुलित करते हैं कि मूल प्रावधान के तहत राज्यपाल द्वारा धन विधेयक को शुरू में ही अस्वीकार किया जा सकता है! वह विधेयक को



तभी लौटा सकते हैं जब वह धन विधेयक न हो। आप इसे कैसे संतुलित करते हैं! इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अनुच्छेद 207 में इसका उतर है। सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अनुच्छेद 207 के अनुसार, धन विधेयक केवल राज्यपाल के प्रस्ताव पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए राज्यपाल द्वारा धन विधेयक को रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यह राज्यपाल की अनुशंसा पर ही

प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, साल्वे ने कहा कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है, जब विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक राज्यपाल द्वारा अनुशंसित संस्करण से भिन्न हो। उन्होंने कहा कि यदि अंततः स्वीकृत किया गया प्रस्ताव राज्यपाल द्वारा



अनुशंसित संस्करण से मेल नहीं खाता है तो राज्यपाल स्वीकृति रोक सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह इस तर्क का परीक्षण काल्पनिक स्थितियों के आधार पर कर रहे हैं। हरीश साल्वे ने कहा कि चूंकि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 207 के रूप में धन विधेयक के संबंध में एक सुरक्षा कवच जोड़ा है, इसलिए उन्होंने धन विधेयकों पर चौथा विकल्प (रोकना) लागू करना जरूरी नहीं समझा होगा। श्री हरिष साल्वे ने कहा कि



नाटककार अजय शुक्ला के दिमाग में ये ख्याल कौंधा कि अगर आज के जमाने में शाहजहाँ ताजमहल बनवाने की सोचे तो क्या होगा? बस, ये सवाल ही काफी था कि उनकी कलम अपने आप चल पड़ी। पात्र जैसे कहीं से अपने आप ही उतर आए, शाहजहाँ को छोड़कर बाकी सब यथार्थ, हमारे समाज से ही जो इस मुल्क की सड़कों, दफ्तरों, तमाम तंत्रों और टेंडर की फाइलों में खुलकर साँस लेते हैं। हालांकि, शाहजहाँ का नाम इस संदर्भ में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ से प्रेरित है, किंतु केवल नाम का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें औरंगजेब नामक पात्र का भी उल्लेख है, जो इतिहास से लिया गया प्रतीत होता है, परंतु वह भी केवल नाम का उपयोग किया गया है।

इस नाटक का प्रथम प्रकाशन अक्टूबर 1998 में दिल्ली के प्रकाशन संस्थान द्वारा किया गया। हालांकि, साल 1993 में नाटककार ने इस नाटक को लिख लिया, किंतु इसका मंचन पाँच साल बाद ही हो पाया। उस दौरान निर्देशक



मध्यप्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (सिया) की कार्यशैली को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।मई 2025 में, सिया ने एक दिन में ही 450 परियोजनाओं को मंजूरी देकर स्वीकृत कर दिया गया था। जबकि आवश्यकता अनुसार साझी बैठक बुलाना अनिवार्य था। इस प्रक्रिया में बैठक आयोजित नहीं की गई, फाइलें जानबूझकर लंबित रखी गईं, और समय सीमा समाप्त होने पर स्वीकृति अपने आप मान ली गई, जो नियमों का उल्लंघन है।इसमें 200 से अधिक परियोजनाएँ खनन विभाग से संबंधित थीं, जिसमें भ्रष्टाचार की गंभीर आशंका है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार, पर्यावरणीय मंजूरी के लिए संबंधित प्राधिकरण की सामूहिक बैठक आवश्यक है। यह नियम पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। तकनीकी मूल्यांकन, जन-सुनवाई जैसी प्रक्रियाओं को अनदेखी हुई। कई मामलों में खनिज की मात्रा या नाम तक बदल दिए गए ताकि गैरकानूनी कृत्यों को कानूनी रूप दिया जा सके। आरोप है कि इस पूरा मामला खनन माफिया और दलालों को फायदा पहुंचाना था। अधिकारियों ने अनुमति प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सिया की स्वायत्तता कमजोर करने का प्रयास किया गया है। अन्य परियोजनाओं की मंजूरी पर भी विवाद उठी-जब सहमति से ये मंजूरियां दी गईं, तब सदस्य सचिव ने असहमति जताई और प्रक्रिया को अवैध करार दिया। 28 मार्च से 21 अप्रैल 2025 तक सिया में कोई बैठक नहीं हुई, सैकड़ों फाइलें लंबित रहीं। अप्रैल-मई 2025 में केवल तीन बैठकें हुईं-लेकिन इनमें भी अधिकांश स्वीकृतियां सदस्य सचिव ने अकेले दीं।

सिया के चेयरमैन शिवनारायण सिंह चौहान ने इन फर्जी मंजूरियों को उजागर किया, कई बार बैठक बुलाने का अनुरोध किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र भेजकर इस प्रक्रिया को गैरकानूनी बताया। साथ ही एफआईआर दर्ज करने की मांग की। चेयरमैन एसएनएस चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को दर किनार कर 237 परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृतियां दे दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सिया

नाक-भौं सिकोड़ते, कुछ कहते – ये ऐतिहासिक है कि सामाजिक?, कुछ और बुदबुदाते कि शाहजहाँ आज ताजमहल क्यों बनवाएगा? इस विषय में अजय शुक्ला खुद लिखते हैं कि जिस भी निर्देशक को नाटक पढ़ने को देता वह बड़ी रोनी-सी सूखत बनाकर लौटा देता। मगर 1998 में एन.एस.डी. रेपेर्टरी ने इसे मंच पर उतारा, और फिर क्या, ये नाटक तो जैसे देशभर में मशहूर हो गया। देश-विदेश के कई भाषाओं में अनुवाद, साथ ही विदेशों में भी मंचन। हम देखें हैं कि तीन दशक बाद भी ये उतना ही जिंदा है, इसलिए भी क्योंकि ये नाटक भ्रष्टाचार की उस नफस को पकड़ता है, जो इस मुल्क को कमजोर कर रही है। नाटक के शुरुआत में अजय शुक्ला इस नाटक को हास्य-व्यंग्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में रखते हैं।कहीं न कहीं ये यह सही ही कहते हैं।

इस नाटक को पढ़कर हम हैंसते हैं, इस पर कई चर्चाएँ करते हैं। मोहन राकेश सम्मान से यह कृति सम्मानित है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, और आधुनिक भारत के श्रेष्ठ नाटकों में शुमार है।किंतु, जब हम इसे ऑफिस, घर, क्लासरूम या मुस्तकालय में पढ़कर या मंचों पर इसे देखकर बाहर कदम रखते हैं, तो वही टेंडर, वही रिश्तत, वही

सिस्टम हमारे सामने होता है। इसकी लोकप्रियता नाटककार, पाठक या निर्देशक को सुख दे या दुख, यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है : जैसा कि अदम गोंडवी ने अपने समय में गजल लिख कर उठाया था –जो उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में, गाँव तक वह रौशनी आणी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, रमसुधी की झोंपड़ी सरपंच की चौपाल में।

नाटक की कहानी इस उपज पर टिकी है कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ, अचानक बीसवीं सदी पर दस्तक देते हैं, और ताजमहल बनवाने की इच्छा जाहिर करते हैं। मगर हम पाते हैं कि इन सबके इर्द-गिर्द सब कुछ आधुनिक, वही सरकारी दफ्तरों की फाइलें, रिश्तत की भेंट चढ़ते हुए अफसर, कुर्सी पर बैठकर सियासत की चालें चलते नेता। हर कदम पर टालमटोल और शाहजहाँ का सपना, जो भ्रष्ट नेताओं व अफसरों की भूलभुलैया में फंसकर रह जाता है। नाटक में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पात्रों की बात-चीत पढ़कर ही हमारे आस-पड़ोस के कथित सम्मानित लोगों के चेहरे याद आ जाते हैं। स्टेट के चीफ इंजीनियर श्रीमान गुप्ता जी सुधीर को कहते हैं – हाँ, वाकई में बहुत बड़ा खेल है। ठीक से खेला जाए तो अरबों में जा सकता

है। जवाब में सुधीर उत्साहपूर्वक कहता है – यानी कि अब तो किस्मत खुल गयी सर जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है, सर खुल गई किस्मत। यह संवाद व्यवस्था की विसंगतियों को बेहद सहज ढंग से उभारता है। जब सिस्टम चलाने वाला ही इसे खेल मानकर खुद उसमें लिप्त हो जाए, तो भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें बन जाती हैं।

चीफ इंजीनियर गुप्ता जी के नेतृत्व में ताजमहल का सपना साकार करने का प्रोजेक्ट शुरू तो हुआ, मगर टेंडर की सूचना जारी करने में पच्चीस वर्ष बीत गए।इन वर्षों में तंत्र के सारे शोषक अपने-अपने लाभ लेने में मशगूल रहे। कॉर्पोरेशन से लेकर सिर पर छत तक, सब कुछ बनवा लिया, मगर ताजमहल? वो तो बस कागजों में ही उभरता रहा, बनने से कोसों दूर। जिस दिन टेंडर की सूचना निकलने की बारी आयी, गुप्ता जी शाहजहाँ को ये खुशखबरी सुनाने निकले : मगर वहाँ पहुँचकर देखा तो शाहजहाँ की रूह कब की दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। नाटक के अंत में स्टेट चीफ इंजीनियर, सुधीर से कहता है, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, सुन लो। वक्त गया बात गई पर हम नहीं जाएँगे। फिर कोई ताज का खाबू देखेगा, तब हम फिर बुलाए जाएँगे, तब ये फाइल फिर काम आएगी।

पर्यावरणीय मंजूरी विवाद की जमीनी स्थिति

मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अंतर्गत अधिसूचित किया है, जिसमें नई परियोजनाओं या गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध और निषेध लगाए गए हैं, मौजूदा परियोजनाओं और गतिविधियों के विस्तार या आधुनिकीकरण पर उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करना है।

की सदस्य सचिव उमा महेश्वर और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव नवीनी कोठारी ने मिलकर प्राधिकरण की बैठकों में देरी की, ताकि खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाया जा सके। आरोप है कि इसके लिए सिया की अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया को भी दरकिनार कर कई प्रोजेक्ट्स को बिना अधिकार स्वीकृति दे दी। 24 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव-प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया। यह नोटिस 237 अवैध पर्यावरणीय मंजूरियों को लेकर जारी किया गया था, जहां सदस्य सचिव द्वारा सिया को बायपास कर स्वीकृतियां दी गई थी। कोर्ट ने पूछा कि ये मंजूरियां बिना सिया की बैठक के कैसे दी गईं, और उनसे दो सप्ताह में जवाब मांगा गया। इस मामले पर विगत सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बहुत गंभीर माना और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि आईएसएस अधिकारी पर्यावरण स्वीकृति जारी करेंगे, तो फिर राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की स्वतंत्र संस्था होने का क्या मतलब रह जाएगा?

मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत अधिसूचित किया है, जिसमें नई परियोजनाओं या गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध और निषेध लगाए गए हैं, मौजूदा परियोजनाओं और गतिविधियों के विस्तार या आधुनिकीकरण पर उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करना है।

अधिसूचना के तहत, कुछ नई परियोजनाओं, मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए, उनके पर्यावरणीय प्रभाव की क्षमता के आधार पर, पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। अधिसूचना की अनुसूची में श्रेणी ‘क’ के अंतर्गत आने वाली

परियोजनाओं के लिए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक है।जबकि श्रेणी ‘ख’ के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए, गतिविधियों की सीमा के आधार पर, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से मंजूरी आवश्यक है। अधिसूचना में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने एक राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन प्राधिकरण (सिया) के गठन का प्रावधान है। सिया की सहायता के लिए, एक राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) का गठन किया गया है। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति परियोजनाओं की जांच करेगी और पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने पर निर्णय लेने हेतु अपनी सिफारिशें सिया को भेजेगी।

पर्यावरण आंकलन अधिसूचना को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत सबसे पहले 1994 में जारी किया गया था। इसके पहले यह कार्य महज प्रशासनिक जरूरत होता था। लेकिन 27 जनवरी 1994 में पर्यावरण प्रभाव नोटीफिकेशन के जरिये एक विस्तृत प्रक्रिया शुरू किया गया।इस नोटीफिकेशन के अन्तर्गत 32 औद्योगिक एवं विकासात्मक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया। जिसमें बड़ेबांध, माईंस, एयरपोर्ट, हाइवे,समुद्र तट पर तेल प्वं गैस उत्पादन, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कीटनाशक उधोग, रसायनिक खाद, धातु उधोग, थर्मल पावर प्लांट, परमाणु उर्जा परियोजना आदि शामिल है। परियोजनाओं को एक विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक बनाया गया। जिसके तहत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट (ई.आई.ए) तैयार कर सार्वजनिक करना एवं जन सुनवाई महत्वपूर्ण माना गया। ई.आई.ए रिपोर्ट अंग्रेजी तथा प्रादेशिक और स्थानिय भाषा में जिला मजिस्ट्रेट, पंचायत व जिला परिषद, जिला उधोग कार्यालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय

में उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का केवल सही- सही आंकलन ही न हो बल्कि इस आंकलन प्रक्रिया में प्रभावित समुदायों का मत भी लिया जाए और उसी के आधार पर परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देना या नहीं देने का फैसला लिया जाए। इस अधिसूचना के अंतर्गत ही प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरणीय जन सुनवाई जैसा महत्वपूर्ण प्रावधान रखा गया है। किसी भी परियोजना को मंजूरी देने से पहले उसके प्रभावों को पैनी नजर से आंकने और जांचने के रास्ते भी खुले और निर्णय प्रक्रिया में जनता की भूमिका भी बढी। इस प्रक्रिया में परियोजना चार चरणों से गुजरती है। जब परियोजना निर्माता आवेदन करता है, उसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रतीक्षारत अवस्था कहते हैं।इसके बाद एक विशेषज्ञ आकलन समिति द्वारा परियोजना की छानबीन की जाती है। छानबीन के अन्तर्गत पर्यावरण प्रभाव आंकलन हेतु बिंदु (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) तैयार किए जाते हैं। इसी के साथ परियोजना टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्वीकृत अवस्था में आ जाती है।पर्यावरण प्रभाव आंकलन का मसौदा तैयार होने के बाद जन सुनवाई आयोजित की जाती है और उसके बाद पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना को अंतिम रूप दिया जाता है। ये सारे चरण पूरे होने के बाद रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती है। यह अवस्था पर्यावरण मंजूरी प्रतीक्षारत अवस्था है। इसके उपरांत विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा संबंधित दस्तावेजों की छानबीन की जाती है और परियोजना को स्वीकृत या खारिज की करने की सिफारिश करती है। एक बार पर्यावरण मंजूरी मिल जाने के बाद परियोजना पर्यावरण मंजूरी अवस्था में आ जाती है।पू्जी एवं कम्पनीयों के सामने झुकने वाली सरकार की मंशा विपरित होने के कारण 1994 से 2006 तक 12 सालों में 13 बार संशोधन किया गया। 14 सितम्बर 2006 को

यदि संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल के विकल्पों पर कोई सीमाएं नहीं लगाईं तो व्याख्या के जरिए ऐसी सीमाएं नहीं जोड़ी जा सकतीं। उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा तय करने के भी खिलाफ तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई। योजना के पीछे राजनीतिक प्रक्रिया होती है। हम पन्द्रह दिनों में इसे पूरा कर लेते हैं। लेकिन, कुछ मामलों में इसमें 6 महीने लग जाते हैं। यह कोई छुपकर बैठकर निर्णय लेने जैसा नहीं हो सकता।

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद धारण करते हैं। हमें यह समझना होगा कि यह संविधान के अंतर्गत है। वह वस्तुतः अपनी इच्छा पर ही पद धारण करते हैं। एक अर्थ में, वह संघ और राज्य के बीच संवाद का माध्यम हैं। ऐसे में यह मानना कठिन है कि जब संघ विधेयक को स्वीकार नहीं करता और राज्यपाल उसे रोक लेते हैं तो यह मानना भी कठिन होगा कि संघ की कोई भूमिका नहीं है। संविधान इसी तरह काम करता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि न्यायालय इस बात की समीक्षा नहीं कर सकता कि राज्यपाल ने अपनी सहमति क्यों नहीं रोकी। यदि प्रावधान में कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं हैं तो ऐसे कोई न्यायिक रूप से प्रबंधकीय मानक नहीं हैं, जिनके आधार पर शक्ति के प्रयोग की समीक्षा की जा सके। मुख्य न्याधिपति के इस स्पष्ट प्रश्न कि ‘क्या न्यायालय राज्यपाल से पूछ सकता है कि वह आदेश क्यों रोक रहे हैं?’ के उत्तर में साल्वे ने जोरदार तरीके से ‘नहीं’ कहा। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट नीरा जे किशन कौल और मनिंदर सिंह ने भी केंद्र सरकार की दलीलों का समर्थन करते हुए तर्क दिए।

(शेष अगले कॉलम में)

समझ गए। चलो अब यहाँ से चलते हैं। नाटक का व्यंग्य आज के सरकारी तंत्र की कमियों पर है। शाहजहाँ के पुराने दौर की नजर से देखने पर यह और भी गहरा लगता है। हँसी-मजाक व व्यंग्य के बीच नाटक उस निराशा को उजागर करता है, जो स्वा्थी लोगों ने आजादी के बाद के भारत में फैलाई है। नाटक के अंत में चीफ इंजीनियर की बातों से यह साफ झलकता है कि ताजमहल जैसा टेंडर आज बिक रहा है, कल भी बिकेगा, और सम्भवतः यों ही भविष्य में भी बिके, क्योंकि इस मुल्क में भ्रष्टाचार का बाजार सूना होता तो नहीं दिख रहा। फिर भी, कहीं न कहीं दिल में एक उम्मीद है कि शायद कोई सुबह आए, जब ये सब बदल जाए। नाटक के पन्ने पलटते-पलटते आखिर में अदम गोंडवी का लहजा फिर दिल में गूँज उठता है, मानो नाटककार भी हम सभी से कह रहे हों – जिसम क्या है, रुह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती है इस दुनिया के मौसम का मिज़ाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। जल रहा है देश, यह वहला रही है कौम को, किस तरह अश्लील है संसद की भाषा देखिए।

सक्षिप्त समाचार

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सब जेल मुलताई में स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित

बैतूल (निप्र)। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को सब जेल मुलताई में बंदियों में कुष्ठ रोग से संबंधित शंकाप्रद रोगियों की जांच के लिए शिविर आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुसमाड़े ने बताया कि शिविर में 103 बंदियों की जांच जिला स्तरीय कुष्ठ रोग दल के श्री राजेश मेहता एवं श्री लिखीराम सागरे एनएमए द्वारा की गई, जिनमें से 13 बंदियों को चर्म रोग से संबंधित समस्या पाई गई, जिन्हें दवाईयां वितरित की गई। किसी भी बंदी में कुष्ठ रोग के लक्षण नहीं पाए गए। शिविर में कुष्ठ रोग से संबंधित जानकारीयां प्रदाय की गई। शिविर में जेल फार्मासिस्ट श्री दीपक पंवार मौजूद रहे।

अधिकारियों द्वारा किया गया पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण



सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निदेशानुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले के पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में अधिकारियों द्वारा सीहोर के तुनिया चौराहा स्थित वर्मा प्युलस एंड सर्विस पेट्रोल पंप का निरीक्षण कर जांच की गई। जांच के दौरान अंडग्राउंड डीजल के टैंक में भण्डारित 5,944 लीटर डीजल में 10.5 सेमी पानी की मात्रा पायी गई और 04 प्रतिशत से अधिक अंतर तक की अनियमितता पाई गई। इसके साथ ही ऑनलाइन स्टॉक से डीजल के स्टॉक में अंतर पाया गया। पेट्रोल पंप पर मुफ्त हवा, शौचालय, पेयजल, अविन शमन यन्त्र की वैधता भी समाप्त पाई गई। अधिकारियों द्वारा पेट्रोल पंप पर अनियमितताएं पाए जाने पर डीजल की मशीन को सील कर दिया गया है और पेट्रोल पंप से 5,45,081 रुपये मूल्य का 5,944 लीटर डीजल जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई जिला अपूर्ती अधिकारी, नापतौल निरीक्षक एवं कनिष्ठ अपूर्ती अधिकारी द्वारा की गई।

राष्ट्रीय खेल दिवस पर कलेक्टर-एसपी ने टेबल टेनिस खेलकर खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित



सीहोर (निप्र)। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर चर्च ग्राउंड स्थित इंडोर हॉल परिसर में अनेक खेल गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री बालागुरू के. तथा एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला शामिल हुए। इस अवसर पर कलेक्टर श्री बालागुरू के. और एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला ने खेल गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स सामग्री किट भी प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए टेबल टेनिस भी खेला। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री बालागुरू के. तथा एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला ने कहा कि खेल केवल जीत-हार का नाम नहीं है, बल्कि खेल जीवन में अनुशासन, धैर्य और सहयोग की भावना का पाठ पढ़ाते हैं। खेलों से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक मजबूती भी आती है। उन्होंने कहा कि खेल व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उसे जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों और विद्यार्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कलेक्टर और एसपी द्वारा टेबल टेनिस खेलने से खिलाड़ियों का जोश और भी दौगुना हो गया। इस अवसर पर सभी को खेल गतिविधियों से जुड़कर स्वयं को स्वस्थ बनाने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर खेल अधिकारी श्रीमती रुबिका देवान, श्री मनोज कर्नौजिया, सूबेदार प्राची राजपूत सहित प्रशिक्षक एवं खिलाड़ी उपस्थित थे। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इंडोर खेल परिसर के साथ ही लीबेयर में अनेक खेल गतिविधियां आयोजित की गईं।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बाढ़ राहत, खोज एवं बचाव तकनीक विषय पर प्रशिक्षण सम्पन्न



रायसेन (निप्र)। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को बाढ़ राहत, खोज एवं बचाव तकनीक विषय पर प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। जिसमें आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल से आए विशेषज्ञ द्वारा बाढ़ आने के कारण, बाढ़ आने की संभावना होने पर किए जाने वाले कार्य और बाढ़ आने पर बचाव कैसे करें। इसके बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि कई घण्टों से मूसलाधार बारिश होने या फिर विगत कुछ दिनों से लगातार बारिश होने पर बाढ़ आने की संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति में नदियों व बरसाती नाले से दूर रहना चाहिए। बाढ़ संभावित क्षेत्र में घर होने पर अति आवश्यक वस्तुएं व प्राथमिक किट तैयार रखनी चाहिए तथा किसी भी समय घर खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रशिक्षण में संपर्दश, वज्रपात या आकाशीय बिजली गिरने, भवनों में आग लगने, भूकम्प आदि आपदाएं आने पर किस प्रकार त्वरित रूप से राहत और बचाव कार्य किए जाएं, कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए आदि के बारे में भी विस्तार से बताया गया। कार्यशाला में डिप्टी कलेक्टर, अधीक्षक भू-अभिलेख सहित अधिकारी, कर्मचारी और प्रतिभागी उपस्थित रहे।

कलेक्टर एवं सीईओ ने किया बच्चों को पोषण टोकरी का वितरण

जब बच्चे मजबूत और कुपोषण मुक्त होंगे, तभी समाज और राष्ट्र सशक्त बनेगा : कलेक्टर

►► महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है एक कदम सुपोषण की ओर नवाचार
►► स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों में किया गया 155 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. तथा जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन ने जिला चिकित्सालय के शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) में एक कदम सुपोषण की ओर कार्यक्रम के तहत आयोजित स्वास्थ्य एवं पोषण शिविर में बच्चों को पोषण टोकरी का वितरण किया। सीहोर जिला चिकित्सालय के साथ ही सीहोर ग्रामीण तथा श्यामपुर में भी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में डॉक्टरों द्वारा 155 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर डीईआईसी में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि बच्चों का स्वस्थ और पोषित होना ही हमारे भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। जब बच्चे मजबूत और कुपोषण मुक्त होंगे, तभी समाज और राष्ट्र सशक्त बनेगा। उन्होंने कहा कि पोषण केवल शरीर को ताकत देने का साधन नहीं है, बल्कि यह बच्चों के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास की नींव है। उन्होंने सभी अभिभावकों से आह्वान किया कि हम सब मिलकर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखें। हर एक छोटा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। सुपोषित बच्चा ही सशक्त भारत की पहचान बनेगा। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने



डीईआईसी का निरीक्षण भी किया। उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में कुपोषण को समाप्त करने और पोषण स्तर में सुधार के लिए समन्वित रूप से एक कदम सुपोषण की ओर नवाचार प्रारंभ किया गया है। इस नवाचार के तहत विभाग द्वारा चिन्हकित बच्चों को पोषण टोकरी का वितरण किया जा रहा है। इस पोषण टोकरी में पोषण युक्त मुरमुरा, तिल, मूँगफली, चना, गुड़ आदि को पाउडर रूप में बच्चों को प्रदान किया जा रहा है, ताकि बच्चों के पोषण स्तर में सुधार

इन स्थानों पर लगाए गए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री ज्ञानेश खरे ने बताया कि एक कदम सुपोषण की ओर नवाचार के तहत सीहोर जिला अस्पताल के डीईआईसी केंद्र के साथ ही बिलकिसगांज, दोराहा सेक्टर एवं श्यामपुर में भी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किए गए।

हो सके। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री ज्ञानेश खरे एवं सीएमएचओ डॉ सुधीर कुमार डेहरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

खेलों से टीम भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास का होता है विकास : कलेक्टर

हमारे जीवन में ऊर्जा और उत्साह का संचार करती हैं खेल गतिविधियां : कलेक्टर



सीहोर (निप्र)। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सीहोर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र (एनआईएमएचआर) में अनेक खेल गतिविधियां आयोजित की गईं। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने किया। इस अवसर पर उन्होंने खेल गतिविधियों का शुभारंभ करते हुए दौड़

प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों के दल को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने विद्यार्थियों और प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। खेलों से न केवल शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है, बल्कि टीम भावना,

अनुशासन और आत्मविश्वास का भी विकास होता है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी समान रूप से भाग लेना चाहिए। खेल हमारे जीवन में ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं और व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसके साथ ही हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को मजबूती मिलती है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस हमें महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने खेल से देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर खेलों को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे खेलों को केवल मनोरंजन के साधन के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने व्यक्तित्व विकास और कैरियर के नए अवसरों के रूप में भी अपनाना। इस अवसर पर सभी को अपने जीवन में खेल गतिविधियों से जुड़ने और स्वस्थ रहने की शपथ भी दिलाई गई।

बैतूल बनेगा खेलों का हब: केन्द्रीय मंत्री श्री उईके

केन्द्रीय मंत्री श्री उईके ने खेल दिवस और सांसद खेल महोत्सव के तहत रजिस्ट्रेशन का किया शुभारंभ

बैतूल (निप्र)। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य श्री दुर्गादास उईके ने जिले के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। उनके द्वारा सांसद खेल महोत्सव के तहत खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ भी किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में जिले को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने बताया कि जिले में 5 करोड़ की लागत से क्रिकेट स्टेडियम जल्द बनकर तैयार होगा। इसी प्रकार जिले में ओपन ऑडिटोरियम के लिए 10 करोड़ और मल्टीपल गेम्स स्टेडियम के लिए 15 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की गई है। आने वाले में समय में बैतूल खेलों का हब बनेगा। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वती बाई बारकर, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री हंसराज धुवें, श्री विकास मिश्रा, श्री प्रदीप खंडेलवाल तथा प्रभारी अपर कलेक्टर श्रीमती अनीता पटेल, एसडीएम श्री अभिजीत सिंह, जिला खेल अधिकारी श्रीमती पूजा कुरील सहित अन्य अधिकारी , स्कूली बच्चे एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे। केन्द्रीय मंत्री श्री उईके ने कहा कि युवाओं को खेलों के प्रति चेतना, जागरूकता और खेलों की महता की दिशा में प्रेरित करने के लिए हॉकी के जादूगर श्रद्धेय श्री मेजर ध्यानचंद की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2012 से प्रारंभ खेल दिवस का उद्देश्य देश के महान खिलाड़ियों के योगदान को याद करना, युवाओं में खेल भावना का विकास और राष्ट्र को खेलों के क्षेत्र में सशक्त बनाना है। श्री ध्यानचंद ने हॉकी के मैदान में करिमा दिखाकर भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए और भारत की खेल



प्रतिभा और क्षमता से दुनिया को अवगत कराया। उन्हीं से सभी को प्रेरणा मिलती है कि जीवन में अनुशासन, समर्पण और परिश्रम से लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है।

भारत खेलों के क्षेत्र में नए आयाम छु रहा : केन्द्रीय मंत्री श्री उईके ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व भारत खेलों के क्षेत्र में नए आयाम छु रहा है। उनका मानना है कि खेल केवल पदक तक सीमित नहीं बल्कि राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य का आधार है। जिसे ध्यान में रखते खेलों इंडिया प्रारंभ किया है, जिसमें 3 हजार से अधिक एथलीट विश्व छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। फिट इंडिया मुवमेंट से 10 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। भारत ने खेलों में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। भारत के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक अपने नाम किए। बार्निंगम कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 पदक जीते।

राष्ट्रीय खेल अकादमी में प्रशिक्षण का मिलेगा अवसर

इस क्रम में सांसद खेल महोत्सव की परिकल्पना भी की गई है। यहां महोत्सव ग्राम, विधानसभा एवं जिला इस प्रकार तीन स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रत्येक जिले से 10 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें राष्ट्रीय खेल अकादमी में प्रशिक्षण मिलेगा। सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य नवोदित खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करना, स्थानीय खिलाड़ियों को पहचान दिलाना और युवाओं को अनुशासन, फिटनेस और खेल भावना से जोड़ना है। केन्द्रीय मंत्री श्री उईके ने कहा कि भारत का युवा खेलों के मैदान में जीतता है तो केवल पदक ही नहीं बल्कि देश के गौरव को भी बढ़ाता है।

खेलों से शारीरिक क्षमता वृद्धि, व्यक्तित्व विकास और चरित्र का निर्माण होता है : कलेक्टर



सीहोर (निप्र)। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सीहोर के आवासीय

खेल परिसर में अनेक खेल गतिविधयां आयोजित की गईं। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर श्री बालागुरू के., एसपी श्री दीपक

कुमार शुक्ला, जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन और पैरालंपिक मेडलिस्ट श्री कपिल परमार ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि खेलों से जहाँ एक ओर शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है, वहीं व्यक्ति के चरित्र का निर्माण भी होता है। खेलों से महत्वपूर्ण सीख भी मिलती है, जो खिलाड़ी जीवन के संघर्ष, जिम्मेदारियों और कठिन परिस्थितियों पर विजय पाने में काम आती है। खेलों में भाग लेने से से ऐसी खेल भावना के साथ ही साथ सकारात्मक दृष्टिकोण का भी विकास होता है।

खेल भावना के कारण ही हार और जीत को सहजता से लिया जाता है और परस्पर मैत्री भाव का विकास होता है। उन्होंने कहा कि आज पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी जरूरी है। विगत कुछ वर्षों से खेलों में कैरियर के अवसरों में विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए खेलों का महत्व हर आयु वर्ग में समान रूप से जरूरी है। खेल न केवल शरीर को सक्रिय बनाए रखते हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कारगर साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को शारीरिक गतिविधियों की जरूरत है। बच्चों के लिए खेल, सीखने और अनुशासन का साधन है, तो

युवाओं के लिए फिटनेस और टीमवर्क की भावना का आधार है। वहीं बुजुर्गों के लिए हल्के-फुल्के खेल और व्यायाम लंबे समय तक तंदुरुस्ती बनाए रखने में मदद करते हैं। कार्यक्रम में एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला ने कहा कि आज मेजर ध्यानचंद की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि खेलों और फिटनेस के प्रति लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि देश के अनेक खिलाड़ियों को उनकी खेलों में अभूतपूर्व उपलब्धियों के कारण हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि सीहोर के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है।

पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्यप्रदेश में हो रहे स्पोर्ट्स रिवोल्यूशन का किया उल्लेख



भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश की खेल उपलब्धियों को मन की बात कार्यक्रम में दो बार उल्लेख किया। उन्होंने देश के पहले खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्यप्रदेश द्वारा सबसे अधिक मेडल जीतने पर बधाई दी। साथ ही शहडोल जिले में फुटबॉल के क्रेज और उसके प्रति जर्मनी के कोच द्वारा रुचि लेने और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की भावना का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का मुरैना जिले के पिपरसेवा में श्रवण किया। विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और स्थानीय रहवासी उपस्थित थे।

श्रीनगर की डल झील में हुआ देश का पहला वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल- प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश में पहला खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर की डल झील में हुआ। जहाँ महिला एथलेटिक्स भी पीछे नहीं रही उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें भाग लिया। विशेष बधाई मध्यप्रदेश को, जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते। उसके बाद हरियाणा और उड़ीसा का स्थान रहा।



श्री सारंग ने जताया आभार, कहा- प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलेगी वैश्विक पहचान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 125वें संस्करण में मध्यप्रदेश की 'मिनी ब्राजील' विचारपुर फुटबॉल टीम और वॉटर स्पोर्ट्स टीम की उपलब्धियों की सराहना की। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रदेश के खिलाड़ियों की सराहना किए जाने पर आभार व्यक्त किया। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि यह हम सबके लिए गर्व का क्षण है।

शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों को जर्मनी में मिलेगा प्रशिक्षण- प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जर्मनी के फुटबॉल कोच के शहडोल जिले के फुटबॉल खिलाड़ियों से जुड़ने का प्रसंग मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से साझा किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि एक पांडकास्ट में उन्होंने मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में फुटबॉल के क्रेज से जुड़े एक गांव का वर्णन किया था। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच श्री डिडमार बायर डॉफंड ने सुनी। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की रुचि और प्रतिभा ने फुटबॉल कोच को

प्रभावित किया। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि शहडोल के प्रतिभाशाली खिलाड़ी दूसरे देशों को भी आकर्षित करेंगे। अब जर्मनी के कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। मध्यप्रदेश की सरकार ने भी उनसे संपर्क किया है। जल्द ही हमारे कुछ युवा साथी फुटबॉल का प्रशिक्षण लेने के लिए जर्मनी जाएंगे। भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ रही है। देशवासियों से अपील है कि वे एक बार शहडोल जरूर जाएं और वहां हो रहे स्पोर्टिंग रिवोल्यूशन को करीब से जरूर देखें। भारत में विकास की अनंत संभावनाएं हूँगी है।

विचारपुर के चार खिलाड़ी और एक कोच जर्मनी में लेंगे प्रशिक्षण-

उल्लेखनीय है कि मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध शहडोल के ग्राम विचारपुर की गुंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। यह गौरव विचारपुर के फुटबॉल खिलाड़ियों की लगन, समर्पण और कड़ी मेहनत का नतीजा है। फुटबॉल कोच श्री रईस अहमद ने बताया कि आगामी दिनों में 2 बालक फुटबॉल खिलाड़ी, 2 बालिका फुटबॉल खिलाड़ी एवं 1 फुटबॉल कोच जर्मनी अकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि जर्मनी में होने वाला यह प्रशिक्षण खिलाड़ियों और कोच को न केवल आधुनिक तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगा बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार भी करेगा। विचारपुर की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने एक बार फिर यह सवि्त कर दिया है कि मेहनत, जुनून और सही दिशा में प्रयास करने से ग्रामीण प्रतिभाएँ भी विश्व पटल पर अपनी पहचान बना सकती हैं।

गणेश उत्सव पर स्वदेशी अपनाने का दिया संदेश- प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों को गणेश उत्सव पर स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एक ही मंत्र 'वोकल फॉर लोकल', एक ही रास्ता 'आत्मनिर्भर भारत', एक ही लक्ष्य 'विकसित भारत' के भाव को लेकर हमें आगे चलना है।

भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में चर्चा

‘स्व’ की खोज से ही मिलती है असली स्वाधीनता, सिर्फ स्वतंत्रता से नहीं

भोपाल (नप्र)। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में आयोजित अध्ययन समूह की मासिक श्रृंखला में छात्रों और शिक्षकों ने 'स्व से साक्षात्कार' पुस्तक पर विचार साझा किए। परिचर्चा का केंद्र स्वाधीनता और स्वतंत्रता का अंतर और 'स्व' की असली पहचान रहा।

यह प्रज्ञा प्रवाह अंतर्गत संचालित अध्ययन समूह की 11वीं मासिक बैठक थी। इसमें अरुण कुमार ने लिखित 'स्व से साक्षात्कार' पुस्तक के अध्याय 'स्वत्व के लिए संघर्ष' का वाचन किया। उन्होंने कहा कि हम 'इंडिया' कहते हैं, अपनत्व की भावना कम होती है, लेकिन 'भारत' कहने में ज्यादा आत्मीयता महसूस होती है। यही 'स्व' की असली पहचान है।



क्रांतिकारियों का संघर्ष इसी स्व के लिए

चर्चा में यह बात प्रमुखता से उभरी कि स्वाधीनता और स्वतंत्रता में मूलभूत अंतर है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों से मुक्ति है, जबकि स्वाधीनता का मतलब है अपने मूल्यों, आत्मा और संस्कृति के अनुरूप जीवन जीना। वक्ताओं ने कहा कि यही सोच भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बनी। आंदोलन की प्रेरणा स्व त्रयी स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज से मिली। खासकर बंगाल के क्रांतिकारियों का संघर्ष इसी स्व के लिए बड़ी भूमिका निभाता रहा।

युवा हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार

परिचर्चा में अमृतकाल को भी आत्म चेतना और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का समय बताया गया। इसे उस सुबह की घड़ी से जोड़ा गया, जब पूरी तरह उजाला नहीं हुआ होता, लेकिन अंधेरा भी समाप्त हो चुका होता है। इसी प्रतीकात्मकता को आज के भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया। चर्चा में यह बात भी जोर देकर कही गई कि आज का युवा हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, जरूरत सिर्फ सही दिशा देने की है। इस अवसर पर राजनीति विज्ञान, समाज कार्य और समाजशास्त्र विभाग के शिक्षक प्रो. कुमारेश कश्यप, डॉ. सविता सिंह भदौरिया, डॉ. अंजुम आरा, किरण बिलौनिया, डॉ. रौफ, डॉ. कायनात तस्नुम और डॉ. राधा मिश्रा उपस्थित रहे।

हाईवे की चिता सजाकर खराब सड़क का विरोध, चक्काजाम किया

शुजालपुर-आष्टा एनएच-752 पर 1 किमी लंबा जाम ; एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां फंसीं

शुजालपुर (नप्र)। शुजालपुर के फ्रीगंज में नेशनल हाईवे-752 सी पर रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने चक्काजाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने सार्वजनिक अर्थी बनाकर सड़क पर ही हाईवे की चिता सजा डाली। लोगों ने गड़्डों को लेकर विलाप किया और सरकार-प्रशासन की बेरखी पर गुस्सा जताया। रहवासियों ने सड़क की तत्काल मरम्मत कराने की मांग



की। लोगों ने कहा कि गड़्डों में गिरकर कई लोग घायल हो चुके हैं। हाइवे का शिकार बन चुके लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के चलते एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 35 मरीजों और बुजुर्गों को लेकर नेत्र शिविर जा रही एम्बुलेंस भी आधे घंटे तक जाम में फंसी रही। हाईवे से लगे फ्रीगंज क्षेत्र में कई जगहों पर बड़े गड़्डे स्थानीय लोगों का कहना है कि आष्टा से पंचोर को जोड़ने वाले इस हाईवे से लगे फ्रीगंज इलाके में कई जगहों पर बड़े गड़्डे हैं। इन गड़्डों में पानी भर जाता है। सड़क किनारे स्थित गणेश पंडालों तक गाड़ियों के पहियों से कीचड़ उछलकर पहुंच रहा है।

महेश्वर में गुंजा, ‘आला रे आला सचिन आला’

क्रिकेटर तेंदुलकर पत्नी-बेटी के साथ यात्रा पर पहुंचे; फैंस एक नजर देखने को उमड़े

महेश्वर (नप्र)। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ दो दिन की निजी यात्रा पर महेश्वर पहुंचे। उन्हें देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा थे। उन्हें देखते ही क्रिकेट प्रेमियों ने 'आला रे आला सचिन आला' और 'भारत का रत्न कैसा हो, सचिन जैसा हो' जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रशंसक उनके साथ एक तस्वीर खिंचवाने और सेल्फी लेने के



लिए बेताब दिखे। सचिन ने भी सहजता दिखाते हुए कुछ देर तक लोगों के साथ फोटो खिंचवाई, लेकिन बड़्की भीड़ के कारण उन्हें काफी मशक़त करनी पड़ी। सचिन पत्नी डॉ. अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ महेश्वर के अहिल्या फोर्ट हैरिटेज होटल में ठहरे हैं। वे महेश्वर और आसपास के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। उनके कार्यक्रम में महारानी अहिल्याबाई का महल और किला, नर्मदा आरती और भावान काशी विश्वनाथ और राजराजेश्वर मंदिर के दर्शन भी शामिल हैं।

सरेराह लड़की का हाथ पकड़ा, खींचकर ले जाने लगा जबलपुर में छेड़छाड़ के बाद दो पक्षों में पथराव, 4 थानों की पुलिस पहुंची



जबलपुर (नप्र)। जबलपुर में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के बाद दो पक्ष आमने-सामने हो गए। आरोपी लड़की का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव चले। 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। एक पक्ष ने आरोपी को पीटते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान आरोपी पक्ष के लोग पुलिस से भिड़ गए। काफी मशक़त के बाद पुलिस आरोपी को ले गई।

घटना बाबा टोला इलाके में शनिवार शाम की है। इसका वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद बाबा टोला इलाके के लोगों ने हनुमानताल थाने का घेराव कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में खुलेआम शराब, जुआ और स्मैक का धंधा चल रहा है। पुलिस को सख्त कदम उठाना चाहिए। वहीं, रविवार को कोर्ट ने छेड़छाड़ के

आरोपी को जेल भेज दिया है। **सरेराह लड़की का हाथ पकड़ा था-** नाबालिग शनिवार शाम को कॉलेज से लौटते समय अपनी सहेलियों के साथ घर पैदल जा रही थी। इसी दौरान मोहम्मद समीर अंसारी उर्फ बब्बू खटीक ने उसका रास्ता रोक लिया। जबरन बात करने के लिए उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। लड़की ने विरोध करते हुए किसी तरह हाथ छुड़ाया और घर पहुंची।

इसके बाद लड़की के परिवार के लोग मोहम्मद समीर के घर पहुंच गए। जहां दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। विवाद की सूचना मिलते ही हनुमानताल, घमापुर, बेलबाग और गोहलपुर थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। यहां लोगों को समझाझपड़ा गई। इस दौरान पुलिस की कुछ लोगों से झड़प हो गई।

समीर ने पोती का दुपट्टा पकड़कर खींचा

छेड़छाड़ पीड़िता की दादी ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब सिंधी कैप से बाबा टोला के बीच लड़कियों के साथ छेड़छाानी की घटना हुई हो। मोहम्मद समीर ने अपने दो दोस्तों के साथ तीनों ने लड़कियों का रास्ता रोका। समीर पोती का दुपट्टा पकड़कर जबरन सड़क से किनारे ले जाने लगा। लड़कियों ने विरोध करते हुए शोर मचाया, जिसके बाद वहां भीड़ जुट गई। इसके बाद आरोपी और उसके दोनों साथी मौके से फरार हो गए।

लड़की की दादी ने आरोप लगाया कि मोहम्मद समीर का पूरा परिवार अवैध कार्यों में लित है। उनके घर से स्मैक, गांजा और शराब बेची जाती है।

छेड़छाानी करने वाला गिरफ्तार

एएसपी जितेंद्र सिंह ने बताया, बाबा टोला में दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। विवाद को शांत करवाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद समीर के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। फिलहाल क्षेत्र में शांति है।

सुरेश पचौरी की पत्नी के रिटायरमेंट पार्टी में दिखे कमलनाथ

दिल्ली में हुए समारोह में सीएम डॉ. मोहन यादव और दिग्गज नेता भी रहे मौजूद



भोपाल (नप्र)। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच सरकार गिरने को हुई बयानबाजी और टिवटर वॉर के बीच पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी की पत्नी सुपर्णा पचौरी (आईएसएस) के सेवानिवृत्ति समारोह में पूर्व सीएम कमलनाथ नजर आए।

दिल्ली के होटल अशोकाम में 28 अगस्त को हुए समारोह में पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, मप्र के सीएम डॉ. मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल, केन्द्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, कांग्रेस छोड़कर

बीजेपी में शामिल हुए नेता प्रमोद कृष्णम, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, होशंगाबाद सांसद चौधरी दर्शन सिंह सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी और नेतागण शामिल हुए। इस समारोह की तस्वीरें अब सामने आई हैं।

पिछले साल बीजेपी में शामिल हुए थे सुरेश पचौरी- कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने पिछले साल मार्च में लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी जॉइन कर ली थी। इसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनपर हमले किए थे। लेकिन,

सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी कांग्रेस नेताओं से अच्छे संबंध हैं। पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए प्रमोद कृष्णम और पूर्व सीएम कमलनाथ एक साथ दिखे।

पशुपालन विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी से रिटायर हुई हैं पत्नी- सुरेश पचौरी की पत्नी सुपर्णा पचौरी केन्द्रीय पशुपालन मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुई हैं। वे वित्त सलाहकार भी रहीं हैं। कई महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी अहम भूमिका रही है।

इंदौर में 3 इंच से ज्यादा बारिश, खरगोन भी तरबतर

प्रदेश के निमाड़ में शनिवार को बादल जमकर बरसे। इंदौर में 3.1 इंच पानी गिर गया। वहीं, खरगोन में डेढ़ इंच बारिश हुई। गुना में आधा इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। ग्वालियर, पचमढ़ी, रतलाम, बालाघाट, हरदा, श्योपुर, मंदसौर, धार में भी हल्की बारिश का दौर जारी रहा। रात में भी कई जिले भीगे।

शाजापुर में तेज गरज-चमक के साथ बारिश

शाजापुर में रविवार दोपहर तेज गर्जन-चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 23 डिग्री रहा।

मौसम विशेषज्ञ सत्येंद्र धनोतिया ने अगले दो दिन रुक-रुककर बारिश की संभावना जताई। चोलार बांध में 6 फीट पानी भर चुका है। जिले में अने तक 18 इंच बारिश हुई, जो पिछले वर्ष की 30 इंच वर्षा से काफी कम है।

भी है। इस वजह से शनिवार को इंदौर समेत कई जिलों में तेज बारिश का दौर बना रहा। रविवार को भी सिस्टम का असर देखने को मिला। इसलिए कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।